page 1 and 8 Apr 21_page 1 Mar 25 final ds.qxd 4/21/2026 2:09 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 रॉयल लीजेंड क्लब ने 15.1 ओवर में हासिल की आसान जीत

5 शेफाली वर्मा 100 टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पांचवी भारतीय महिला बनीं

8 ईश्वर भक्ति और विद्वानों का संग ही सच्चे सुख का मार्ग : स्वामी राम स्वरूप जी

मौसम जम्मू — न्यूनतम 21 — अधिकतम 32

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-96 | जम्मू तवी, मंगलवार 21 अप्रैल, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

जम्मू बस स्टैंड पर कंटीली तारों को लेकर दुकानदारों में मतभेद

जम्मू,, 20 अप्रैल । जम्मू के मुख्य बस स्टैंड पर लगाए गए कंटीले तारों को लेकर दुकानदारों के बीच मतभेद सामने आए हैं। कुछ दुकानदार इन तारों का विरोध कर रहे हैं और इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं जबकि अन्य दुकानदार सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन्हें बरकरार रखने के पक्ष में हैं। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस होती रही, वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों की बातें सुनीं और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की।

पश्चिम एशिया संकट के बीच ग्रामीण योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में जुटी सरकार

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और उसके कारण वैश्विक सप्लाई चेन, वस्तुओं की कीमतों तथा महंगाई पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशभर में चल रही प्रमुख ग्रामीण कल्याण और आधारभूत ढांचा योजनाओं की समीक्षा की है। मंत्रालय ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण, सड़क विकास और जल संरक्षण योजनाओं पर संभावित असर की लगातार निगरानी कर रहा है। लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले, फंड की उपलब्धता बनी रहे और योजनाओं का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सोमवार को इंटर मिनिस्टीरियल पत्रकार वार्ता में ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने बताया रोजगार और मजदूरी सुरक्षा

उधमपुर बस हादसे में 21 लोगों की मौत, 29 घायल

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने जताया शोक

उपराज्यपाल-सीएम ने तत्काल सहायता का दिया आश्वासन- मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख एवं घायलों के लिए 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा

जम्मू, 20 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार को एक यात्री बस पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 अन्य घायल हुए हैं। सबसे पहले बस ने एक ऑटो-रिक्शा को कुचला और फिर सड़क से पलट कर खाई में जा गिरी। अधिकारियों ने बताया कि ऑटो-रिक्शा में सवार लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन वे बच गए।

सुबह करीब 10 बजे रामनगर क्षेत्र के पहाड़ी पर स्थित कागोर्त गांव के पास एक खतरनाक मोड़ पर निजी बस के चालक के नियंत्रण खो देने के बाद पहाड़ी से गुजर रहे सेना के काफिले ने बचाव अभियान का नेतृत्व किया। बस में 50 यात्री सवार थे जिनमें से अधिकांश रामनगर से उधमपुर जा रहे थे और अपने दैनिक काम पर लौट रहे थे। बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ क्योंकि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसका ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से टूट गया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों और घायलों के परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया। उधमपुर-रियासी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि रामनगर से उधमपुर जा रही एक बस पहाड़ी रास्ते पर नियंत्रण खो बैठी और ढलान से नीचे गिर गई और सड़क पर पलटते हुए एक ऑटो-रिक्शा को कुचल दिया। मौके पर ही 15 यात्रियों को मृत पाया गया जबकि 4 अन्य ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दो और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। शर्मा ने कहा कि बचाव कार्य के दौरान स्थानीय निवासियों ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रामनगर एसएचओ और अन्य अधिकारियों सहित पुलिस दल मौके पर पहुंचे। सेना के जवानों ने भी सहायता की और संयुक्त बचाव अभियान चलाया गया। डीआईजी ने बताया कि बाद में हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से वाहन को सीधा किया गया। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद दुखद घटना है और हम अपनों को खोने वाले परिवारों के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस इस दुख की घड़ी में उनके साथ है।

भारत-दक्षिण कोरिया 2030 तक व्यापार को 50 अरब डॉलर तक ले जायेंगे

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिली है। भारत और दक्षिण कोरिया आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करते हुए आपसी व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने को लेकर समहत हुए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने नई दिल्ली में सार्थक और व्यापक बातचीत की। बातचीत के बाद दोनों नेता कई समझौतों और व्यवस्था के आदान-प्रदान के साक्षी बने।

वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत-दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई कुल प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, वित्तीय सेवाओं, जहाज़ निर्माण, एआई, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, रक्षा और सुरक्षा, साथ ही लोगों के बीच और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार 'भारत-दक्षिण कोरिया स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' के तहत संयुक्त दृष्टि पत्र, शिपबिल्डिंग, समुद्री लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास पर अहम समझौते हुए। साथ ही, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को उन्नत करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की घोषणा की गई। दोनों देशों ने पोर्ट्स, स्टील सप्लाई चेन, एमएसएमई, विज्ञान-प्रौद्योगिकी और डिजिटल ब्रिज जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय सहयोग के तहत एनपीसीआई और कोरियाई संस्थान के बीच भुगतान प्रणाली को लेकर समझौता हुआ। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, पेरिस समझौते के तहत सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2026-2030), खेल और रचनात्मक उद्योगों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा संवाद शुरू करने, इंडो-पैसिफिक पहल में कोरिया की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने जैसे कदमों की घोषणा की। वर्ष 2028-29 को भारत-कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) पी. कुमारन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत यात्रा के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

साइबर अपराध से निपटने के लिए रियल टाइम तंत्र जरूरी : सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के 22वें डीपी कोहली स्मृति व्याख्यान में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने साइबर अपराधों पर प्रभावी एवं वास्तविक समय में कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवा (एमएसएम) पदक से कुल 23 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

यहां भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायपालिका के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साइबर अपराध अब बेहद संगठित और तेज हो गए हैं, जबकि उनकी जांच और प्रतिक्रिया अभी भी धीमी है। साइबर ठगी आमतौर पर एक कॉल या संदेश से शुरू होती है, जिसमें लोगों को झांसे में लेकर उनकी निजी या बैंकिंग जानकारी हासिल की जाती है और कुछ ही समय में धनराशि कई खातों में ट्रांसफर

कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए रियल टाइम सूचना साझा करना, संदिग्ध लेन-देन पर तुरंत रोक लगाना और जरूरत पड़ने पर खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज करने जैसी व्यवस्थाएं विकसित करनी होंगी। साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों, दूरसंचार कंपनियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि अपराध को समय रहते रोका जा सके।

मुख्यमंत्री उमर द्वारा जम्मू-पुंछ राजमार्ग पर 2.7 किलोमीटर लंबी सुंगल सुरंग की प्रगति की समीक्षा

जम्मू, 20 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को जम्मू-पुंछ राजमार्ग पर 2.79 किलोमीटर लंबी सुंगल सुरंग परियोजना पर चल रहे काम की समीक्षा की जो इस साल के अंत में पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नौशेरा जाते समय मुख्यमंत्री ने आज सुंगल सुरंग परियोजना पर चल रहे काम का निरीक्षण किया और साइट पर प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दौरान अधिकारियों ने उन्हें खुदाई संरचनात्मक कार्य और संबंधित सड़क विकास सहित निर्माण की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। सुंगल सुरंग जो अखनूर और पुंछ को जोड़ती है, एक प्रमुख निर्माण मील का पत्थर हासिल करने के लिए रणनीतिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार सुरंगों में से दूसरी है, जिसे गोल्डन आर्क रोड के रूप में जाना जाता है 2.79 किलोमीटर लंबी सुरंग एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में अखनूर और पुंछ के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना पूरी होने वाली है और सीमा सड़क संगठन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। गोल्डन आर्क रोड, लगभग 200 किलोमीटर लंबा रणनीतिक खंड, दक्षिण कश्मीर को पश्चिमी जिलों से जोड़ता है और अखनूर, राजौरी और पुंछ सहित प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ता है। अधिकारियों ने कहा कि राजमार्ग में चार प्रमुख सुरंगें शामिल हैं कंडी, सुंगल, नौशेरा और भिंबर गली जिन्हें कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्र में हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

जम्मूकश्मीर में औद्योगिक क्रांति की तैयारी- नई नीति पर मंथन शुरू

जम्मू 20 अप्रैल। जम्मूकश्मीर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में आसानी) और नई औद्योगिक नीति के संशोधन पर बनी समिति ने आज यहाँ उद्योग भवन में हितधारकों के साथ अपनी पहली बैठक की। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने जम्मू संभाग के विभिन्न औद्योगिक और व्यापार संघों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में समिति के सदस्य विक्रमजीत सिंह, आयुक्त सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग और अमिताभ चटर्जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, जेएंडके बैंक ने भाग लिया।

केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति को संशोधित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने पर हितधारकों के साथ समिति का यह पहला परामर्श था। अगली बैठक कश्मीर में आयोजित की जाएगी। विचार-विमर्श के दौरान, उद्योग प्रतिनिधियों ने व्यापक मुद्दों पर विस्तृत फीडबैक दिया। सुझावों में नियामक सरलीकरण, अनुपालन बोझ को कम करने, वित्त तक पहुँच में सुधार, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और मौजूदा इकाइयों के विकास का समर्थन करते हुए नए निवेश को आकर्षित करने के लिए तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

किसानों के हित में सरकार का बड़ा फैसला, 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं निर्यात को मंजूरी

नई दिल्ली, 20 अप्रैल। भारत सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अतिरिक्त गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इस कदम से सरकार की वह प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है, जिसके तहत वह किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ घरेलू बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय मौजूदा उत्पादन, स्टॉक की उपलब्धता और कीमतों के रुझानों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया है। रबी 2026 सीजन के दौरान गेहूं की खेती का रकबा बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल यह 328.04 लाख हेक्टेयर था। यह बढ़ोतरी गेहूं की खेती में किसानों के मजबूत भरोसे को दिखाती है, जिसे सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मजबूत खरीद व्यवस्था का सहारा मिला है। साथ ही, यह एक और अच्छी फसल होने की संभावना का भी संकेत देती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 10 मार्च 2026 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का उत्पादन 1202 एलएमटी अनुमानित है। उत्पादन की संतोषजनक संभावनाओं और स्टॉक की अधिक उपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त निर्यात की अनुमति देना उचित समझा गया। इससे पहले, डीएफपीडी ने जनवरी 2026 में 5 एलएमटी गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी थी। इसके बाद, फरवरी 2026 में अतिरिक्त 5 एलएमटी गेहूं उत्पादों और 25 एलएमटी गेहूं के लिए और मंजूरी दी गई।

छात्र की मौत पर जीसीडब्ल्यू गांधी नगर के बाहर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, लापरवाही का आरोप लगाया

जम्मू, 20 अप्रैल। हाल ही में एक दुर्घटना में एक छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को जम्मू में सरकारी महिला कॉलेज (जीसीडब्ल्यू) गांधी नगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज परिसर के बाहर एकत्र हुए नारे लगाए और इस घटना पर गुस्सा व्यक्त किया जिसे उन्होंने लापरवाही के कारण घटना के लिए जिम्मेदार बताया।

यह विरोध राजकीय महिला कॉलेज गांधी नगर जम्मू की चौथे सेमेस्टर की छात्रा अंजलि चौधरी की मौत के बाद हुआ है जिसने कुछ दिन पहले कॉलेज यात्रा के दौरान चलती बस से गिरने के बाद अपनी जान गंवा दी थी। छात्रों ने जवाबदेही की मांग की और अधिकारियों से जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त

कार्रवाई करने का आग्रह किया। विरोध तेज होने पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। स्थिति कुछ समय तक तनावपूर्ण रही छात्रों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा जबकि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन पर नजर रखी।

राणा ने जम्मू-कश्मीर में एफआरए अनुपालन की फास्ट-ट्रैकिंग, सुव्यवस्थित करने का दिया निर्देश

जम्मू, 20 अप्रैल। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनुपालन तंत्र में तेजी लाने और सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया। केंद्र शासित प्रदेश में अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रगति का आकलन करने के लिए जम्मू में सिविल सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश जारी किए गए। बैठक में आयुक्त सचिव वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, शीतल नंदा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक सर्वेश राय जनजातीय कार्य विभाग के सचिव प्रसन्ना रामास्वामी जी निदेशक जनजातीय मामले जम्मू-कश्मीर, मो. मुमताज अली निदेशक वित्त, जनजातीय कार्य विभाग इफ्तिखार चौहान और नोडल अधिकारी, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, डॉ. अब्दुल खबीर, सहित अन्य। अधिक कुशल और पारदर्शी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए मंत्री ने अधिकारियों को वन अधिकारों की मान्यता में तेजी लाने और जिला स्तर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) कोशिकाओं का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये सेल दावा दस्तावेजीकरण को सुविधाजनक बनाने, अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड को समय पर अपलोड करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राणा ने कहा कि एफआरए कोशिकाओं का गठन तेजी से किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया समयबद्ध, समन्वित और जन-केंद्रित होनी चाहिए जिसमें आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए हर चरण पर स्पष्ट रूप से परिभाषित जवाबदेही होनी चाहिए।अंतर-विभागीय तालमेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली प्रक्रियात्मक देरी और प्रशासनिक बाधाओं को खत्म करने के लिए राजस्व, वन और जनजातीय मामलों के विभागों के बीच सहज अभिसरण का आह्वान किया। यह उल्लेख करना उचित है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस भूमिका में वन विभाग की जगह लेते हुए, अधिनियम को लागू करने के लिए जनजातीय मामलों के विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन भूमि और संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देकर वन-निवास समुदायों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना है। अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए राणा ने अधिकारियों को खारिज किए गए दावों पर व्यापक डेटा संकलित करने का निर्देश दिया साथ ही ऐसी अस्वीकृतियों के विस्तृत कारण भी बताए।

रेल मंत्रालय 18,262 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । रेल मंत्रालय ने गर्मी के मौसम के दौरान बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए देशभर में बड़े पैमाने पर विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की घोषणा की है। 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच कुल 908 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जो मिलकर 18,262 फेरे लगाएंगी। रेल मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इनमें से 660 रेलगाड़ियों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, जो 11,294 फेरे संचालित करेंगी। इससे यात्रियों को अग्रिम बुकिंग और यात्रा योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।

ज़ोनवार आंकड़ों में

दक्षिण मध्य रेलवे 124 रेलगाड़ियों (1,184 फेरे) की मंजूरी और 76 रेलगाड़ियों (324 फेरे) की

अधिसूचना के साथ शीर्ष पर है। पश्चिम रेलवे ने 106 रेलगाड़ियों (2,078 फेरों) को मंजूरी दी है, जिनमें से 92 रेलगाड़ियों (1,667 फेरों) को अधिसूचित किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 76 रेलगाड़ियों (2,245 फेरे) को मंजूरी दी है, जिनमें से 62 रेलगाड़ियों (1,878 फेरे) को अधिसूचित किया गया है। उत्तर रेलवे ने 76 रेलगाड़ियों (2,090 फेरे) को मंजूरी दी है, जिनमें से 56 रेलगाड़ियों (1,535 फेरे) को अधिसूचित किया गया है। मध्य रेलवे ने 74 रेलगाड़ियों (3,082 फेरे) को मंजूरी दी है, जिनमें से 70 रेलगाड़ियों (2,238 फेरे) को अधिसूचित किया गया है। दक्षिण रेलवे ने 72 रेलगाड़ियों (558 फेरे) को मंजूरी दी है, जिनमें से 38 रेलगाड़ियों (133 फेरे) को अधिसूचित किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 64 रेलगाड़ियों (2,711 फेरे) को मंजूरी दी है, जिनमें से 38 रेलगाड़ियों (1,060 फेरे) को अधिसूचित किया गया है।

उत्तर मध्य रेलवे ने 54 रेलगाड़ियों (1,163 ट्रिप) को मंजूरी दी है, जिनमें से 46 रेलगाड़ियों (688 ट्रिप) को नोटिफ़ाई किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने 52 रेलगाड़ियों (814 ट्रिप) को मंजूरी दी है, जिनमें से 34 रेलगाड़ियों (477 ट्रिप) को नोटिफ़ाई किया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 28 रेलगाड़ियों (410 ट्रिप) को मंजूरी दी है, जिनमें से 18 रेलगाड़ियों (88 ट्रिप) को नोटिफ़ाई किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 28 रेलगाड़ियों (408 ट्रिप) को मंजूरी दी है, जिनमें से 18 रेलगाड़ियों (192 ट्रिप) को नोटिफ़ाई किया गया है।

सफलता के लिए जरूरी है प्रशिक्षण

इन्टर्नशिप या ट्रेनिंग सबसे ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सिस के लिए मान्यनें रखती है। अधिकांश प्रोफेशनल कोर्सों में इंटर्नशिप को अनिवार्य माना जाता है। किताबी ज्ञान हासिल कर लेने के बाद जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आप बेहतर काम कर सके। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग के बाद विद्यार्थियों को इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है।

इंडस्ट्री में मिलने वाली इसी प्रैक्टिकल टेऊनिंग को इन्टर्नशिप कहा जाता है। इन्टर्नशिप न की जाए तो रोजगार हासिल करने में बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। काम का सही पाता न होना ही युवाओं को रोजगार से अधिक दिन के लिए दुर रखता है। जब एक कॉलेज स्टूडेंट किसी कंपनी में इंटर्नशिप शुरू करता है, तो पहली बार उसे ऑफिसली माहौल या प्रैक्टिकल वर्क के बारे में जानने का मौका मिलता है। ऑफिस का प्रोफेशनल माहौल कई बार स्टूडेंट्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन कुछ खास तैयारी और अच्छे इंटर्नशिप से आप कंपनी और उसके एंप्लॉइज के साथ एक मजबूत प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना सकते हैं। मुमकिन है कि आगे चलकर इसका फायदा भी आपको जॉब के रूप में मिले।

इन्टर्नशिप वो मौका होता है, जिसे करके प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स करियर संबंधित अनुभव प्रैक्टिकली तौर से प्राप्त करते है। इसके अंर्तगत युवा चुनौतिपूर्ण काम को हाथ में लेकर पूरा कर अपना प्रोफेशनल और पर्सनल तौर से विकास करते है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन्टर्नशिप वो प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को खुलने और काम करने के अच्छे

अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है। उन्होंने जो भी पढ़ाई कॉलेज में पढ़ी होती है उसको इन्टर्नशिप करने के दौरान प्रैक्टिकली तौर से उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। इन्टर्नशिप एक ऐसा मौका होता है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के मेल के साथ काम के माहौल को देखने का भी मौका मिलता है।'' इन्टर्नशिप विद्यार्थियों के सीवी की वेल्यू भी बढ़ता है और तो और जहां युवा इन्टर्नशिप करते है वही से उन्हें काम करने का ऑफर भी मिल जाता है। साथ ही उन्हें कैम्पस रिक्रुटमेंट के दौरान भी काम के कई अच्छे ऑफर्स मिलते है।'' जिस प्रकार कार्य को करने का एक सही ढंग होता है, वैसे ही जीवन को समग्र रूप से जीने का भी एक विशेष ढंग होता है। प्रकृति के प्रभाव में खण्ड दृष्टि का होना अविद्या के कारण पाशविक प्रवाह आदि समग्रता की एकाग्रता को भंग करते हैं। इस एकाग्रता का लक्ष्य है वर्तमान में जीना। प्रत्येक सफलता के पीछे पहला रहस्य सूत्र भी यही है। सारे शिक्षण-प्रशिक्षण का यही लक्ष्य होना चाहिए।

आज एक अच्छी नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दिन-प्रतिदिन कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है, ऐसे में स्टूडेंट्स को मिलने वाली इंटर्नशिप का रोल और भी अहम हो गया है। इंटर्नशिप में अच्छी परफॉर्मेस से जॉब के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके परफार्मेस का नतीजा तो इंटर्नशिप खत्म होने पर आएगा, लेकिन एप्टीट्यूड और नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन का रिजल्ट, तो शुरू के दो-तीन दिनों में ही मिल जाएगा। आप अगर सही ड्रेस सेंस के साथ कंपनी में एंट्री करेंगे, प्रॉपर एटिकेट्स के साथ लोगों से मिलेंगे, तो वहां के लोग भी आपको पॉजिटिव ही लेंगे। प्रशिक्षण का पहला कदम विश्वास ही है। प्रशिक्षक और प्रशिक्षु के बीच विश्वास जरूरी है। इसके लिए प्रशिक्षक की गुणवत्ता पर ही परिणाम टिके होते हैं। विषय के बारे में उसकी समझ कितनी है, भाषा पर उसकी पकड़ कितनी है, प्रशिक्षण के प्रति गंभीरता कितनी है, जीवन के दृष्टिकोण व्यापक हैं अथवा संकीर्ण, समय का पाबंद, विनम्र, धैर्यवान आदि गुण संपन्न है अथवा नहीं। प्रशिक्षक का ध्येय, व्यक्तित्व का आकर्षण, मानवीय संवेदना का होना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना प्रशिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

टिप्स फॉर ट्रेनर

इंटर्नशिप करने के दौरान इंटर्न को कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है जो उसके भविष्य में काम आ सकती है। जैसे--

एक इंटर्न के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही इंटर्नशिप पीरियड के दौरान उन्हें किसे रिपोर्ट करना होगा, यह जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए पहले दिन ही वहां के एचआर मैनेजर से मिलकर इंटर्नशिप की डिटेल्स पता कर लें कि आपको किसके अंडर में इंटर्नशिप करनी होगी, ताकि किसी एक सीनियर के गाइडेंस में काम करने और सीखने का मौका मिल सके।

इंटर्नशिप करने वाले फ्रेशर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वह एबसेंट न हो। इस दौरान समय का खासकर ध्यान जरूरी रखें। इससे आप सीनियर्स और मैनेजमेंट को इंप्रेस कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप काम को लेकर गंभीर हैं।

इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को अच्छा परफॉर्म करना होता है। इससे आगे के लिए मौके बनने के असार बनते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है, जब एक इंटर्न सिर्फ अपने काम से मतलब रखे।

एक स्टूडेंट जब इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में जाता है, तो उसका मकसद सीखना होता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जो असाइनमेंट मिले, उसे एक्सेप्ट करें।इंटर्नशिप के दौरान एक इंटर्न के लिए अच्छी सोशल स्किल्स काफी काम आती हैं। ऑफिस के कलीग्स के साथ दोस्ताना व्यवहार करें।

शिष्य तो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। गुरू उसको जो चाहे बना दे। आज का प्रशिक्षु कई अर्थो में गुरू या प्रशिक्षक से अधिक जानता है। अतः उसका श्रद्धालु होना बहुत कठिन है। वह जागरूक है, विषय के प्रति, किन्तु विषय को जीवन का अंग नहीं मानता। अतः मूल्यों के बारे में चिन्ता मुक्त है। स्वभाव से स्वच्छन्द भी है, जिसे स्वतंत्र बनाना है। भीतर की और बाहर की जीवन शैली को संतुलित किए बिना भी कोई प्रशिक्षण सफल नहीं होगा। विषय को आत्मसात करना तभी जाकर संभव होगा। वर्तमान में रहकर ही प्रशिक्षु औचित्य सिद्ध कर सकता है- प्रशिक्षण का। वर्तमान में ही वह अध्यात्म का आकलन कर सकता है। स्वयं की शक्तियों एवं कमजोरियों को भी समझ सकता है। सत्व, रज, तम प्रकृति के तीनों गुणों का भीतर अध्ययन कर सकता है। अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश को विद्या भाव से दूर कर सकता है। कर्म को अकर्म (ब्रह्म) स्वरूप प्रदान कर सकता है। इसमें प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों का ही कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए। वरना सारा ज्ञान अहंकार से आवरित हो जाएगा। किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार यदि अच्छे प्रशिक्षु के प्रति मन में राग पैदा हो जाए तब भी प्रशिक्षण भटक जाएगा। सही अर्थो में व्यक्ति का प्रशिक्षण का कार्य भी एक तरह की पूजा ही है। पत्थर से मूर्ति बनाकर मंदिर में बिठाना है। पूजा का फल समय की पाबंदी से जुड़ा है। जो समय के साथ बंधना नहीं चाहता चाहती, वह सफलता के द्वार सहजता से कभी नहीं पहुंच सकता। श्रम अलग है, बुद्धि अलग है, भाव अलग है। समय की पाबंदी से इनका कोई लेना-देना यदि है तो बस यही कि समय होते ही इनमें कर्म करने की भूख तीव्र हो उठती है। इधर लोहा गर्म हुआ, उधर चोट मारी कि कार्य पूरा। यह अभ्यास व्यक्ति को उम्र भर के लिए प्रशिक्षु बना देता है, भले ही वह प्रशिक्षण का कार्य करता हो। यही तप है, यही कान्ति है। इसी के स्वेद का नाम अमृत है।

ट्रेनिंग के फायदे

- एक व्यवसायिक माहौल में काम करना का मौका मिलता है।
- प्रोफेशनल नेटवर्क और कन्टैक्ट बढ़ते है।
- पैसा भी कमाये जा सकता है। स्टुडैंट के आत्मविष्वास को बढ़ता है, जिससे उनके स्कील, टेंलेड और क्षमता बढ़ती है। भविष्य के लिए अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं।

बनाएं फ्लावर मेकिंग में कॅरियर

आज हाथ से बने फूलों की डिमांड इसलिए और अधिक रहती है, क्योंकि वे अधिक दिनों तक ताजा दिखते हैं। ?से में जहां कई दिनों तक या लगातार सजावट की जरूरत होती है, वहां हाथ से बने फूलों की अहमियत बढ़ जाती है। इसके अलावा ये फूल झड़ते नहीं हैं, जिससे गंदगी नहीं फैलती। इन्हीं सब कारणों के चलते फ्लावर मेकिंग एक बेहतर कॅरियर विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। डेकोरेशन की बढ़ती मांग और असली फूलों की कमी के चलते आर्टीफिशियल यानी मशीनों व हाथ से बने फूलों का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। ?से में फ्लावर मेकिंग को आप आजीविका का बेहतर साधन बना सकते हैं। झआइए जानते हैं इस फील्ड के बारे में-

जानें फ्लावर मेकिंग को

फ्लावर मेकिंग एक हस्तकला है, जिसमें कोई भी हाथों से तरह-तरह के फूल बना कर बाजार में सप्लाई कर सकता है। इन्हें बनाने के लिए मोती, टिशु पेपर, रिबन, ऑरगेंजा यानी कपड़ा और साटन का इस्तेमाल होता है। इनका उपयोग सजावट के अलावा गिफ्ट पैकिंग, एनवलप मेकिंग, बुके और गुलदस्ते बनाने में भी होता है।

जगह का चुनाव

फ्लावर मेकिंग का काम आप एक छोटे-से कमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो आपको एक हॉल की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप शोरूम बनाएंगे तो आपके काम में इजाफा होगा। हाउसहोल्ड काम होने के कारण आप इसे इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी खोल सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखें कि आपको कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने में कोई दिक्कत न हो।

क्या है लागत

फ्लावर मेकिंग का काम आप 25 से 30 हजार रूपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर यह काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे दो लाख रूपए में यह काम काफी बड़े स्तर पर खोला जा सकता है। काम की तरक्की के लिए अगर आप शोरूम खोलना चाहते हैं या फिर फ्लावर मेकिंग के साथ डेकोरेशन का काम भी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। यानी स्तर के हिसाब से लागत बैठेगी।

तैयार माल की बिक्री

आप अपने द्वारा निर्मित फूलों को यूं तो फूलों के बाजारों में बेच सकते हैं, मगर अच्छी बिक्री के लिए आपको कुछ खास सेलिंग पॉइंट्स पर कॉन्टेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ये सेलिंग पॉइंट होटल, डेकोरेटर, मॉल और रेस्तरां और बड़े-बड़े शोरूम हो सकते हैं।

कैसी है आमदनी

फ्लावर मेकिंग में आमदनी आपकी कार्यक्षमता और मार्केटिंग, दोनों पर निर्भर करती है। छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, तो भी प्रतिमाह 10 से 15 हजार रूपए या इससे अधिक कमा सकते हैं। बड़े स्तर के काम और मार्केट में पकड़ है तो आप 25-30 हजार रूपए से साठ हजार रूपए प्रतिमाह तक कमा सकते हैं। अगर आप डेकोरेशन का काम भी साथ-साथ करते हैं, तब आपकी इनकम और भी अधिक हो सकती है।

प्रशिक्षण अवधि

अधिकतर संस्थानों में एक सप्ताह से एक महीने का कोर्स होता है। किसी में तीन महीने का भी कोर्स मौजूद है, जबकि कुछ संस्थान इसी में डेकोरेशन और फ्लावर मेकिंग से संबंधित हस्तकला शिल्प के हुनर सिखाते हैं। यह कोर्स एक साल का होता है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन में एक सप्ताह से एक माह तक के कोर्स कराए जाते हैं।

जरूरी योग्यता

वैसे तो आपका साक्षर होना पर्याप्त है, लेकिन कुछ संस्थान 10वीं और कुछ संस्थान 12वीं पास होना अनिवार्य मानते हैं। आप अपनी क्वालीफिकेशन, फीस देने की कैपेसिटी और जरूरत के हिसाब से प्रवेश ले सकते हैं।

कैसे लें प्रशिक्षण

खादी ग्रामोद्योग से मान्यता प्राप्त केंद्र से प्रशिक्षण लेने के लिए आपको प्रॉस्पेक्टस खरीदना होगा। इसके अतिरिक्त आप किसी स्थापित फर्म में नौकरी करके भी अनुभव बटोर सकते हैं।

चुनिए ओपन लर्निंग का विकल्प

ऐसा नहीं है कि कॅरियर वही बना पाते हैं, जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं। ओपन लर्निंग से पढ़ाई करके भी आप अपने लिए एक अच्छा कॅरियर बना सकते हैं। कॉलेजों की ऊंची कटऑफ्स या प्रतियोगी परीक्षा पास न कर पाने पर बहुत से स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज से बेशक वंचित रह जाते हैं लेकिन उनके लिए ओपन लर्निंग का विकल्प खुला रहता है। आपके साथ चाहे मुद्दा कम अंकों का हो या आपकी मर्जी का, आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए डिस्टेंस मोड एजुकेशन का विकल्प आपके सामने खुला है।

जॉब का विकल्प

बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए डिस्टेंस मोड की पढ़ाई चुनते हैं क्योंकि उन्हें जॉब का एक्सपीरियंस लेना होता है। वे मानते हैं कि जिस क्षेत्र में वे जाना चाहते हैं, वहां कॉलेज की डिग्री से ज्यादा पेशेवर अनुभव काम आना है। डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करने वाले ये स्टूडेट अपना पूरा फोकस प्रोफेशनल कॅरियर पर रखते हैं।

तैयारी का समय

डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करने वालों के लिए सबसे खास बात यह होती है कि रेगुलर कॉलेज न जाने की वजह से उनके पास दिन में पर्याप्त खाली समय होता है। इस खाली समय का इस्तेमाल वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड से पढ़ाई का यह अर्थ नहीं कि आप पढ़ाई को कमतर आंके। आपके पास खाली समय है और इसका सदुपयोग करके आपको भविष्य की तैयारी करनी है।

ये हैं संस्थान

आजकल कई प्रतिष्ठित संस्थान डिस्टेंस मोड की एजुकेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमे प्रमुख हैं- दिल्ली में इग्नू, दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विवि, राजस्थान में वर्धमान महावीर मुक्त विवि, ज्योति विद्यापीठ महिला विवि, मध्यप्रदेश में देवी अहिल्या विवि, डॉ हरिसिंह गौर विवि, सागर आदि।

प्रोफेशनल कोर्स

डिस्टेंस मोड के कोर्स चुनने के पीछे एक वजह यह भी रहती है कि स्टूडेंट किी प्रोफेशनल कोर्स में पूरा ध्यान लगाना चाहते हैं। यदि आप भी किसी प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग लेने की सोच रहे हैं तो डिस्टेंस मोड की पढ़ाई के साथ दोनों आसानी से मैनेज हो जाते हैं। पढ़ाई का ज्यादा बोझ न होने पर आप फोकस कर पाते हैं।

गणित में हैं कई विकल्प

मैथेमेटिक्स से डरने वालों के लिए यह बेशक एक हौव्वा बना रहता हो लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं और पढ़ते हैं, उनके लिए यह कॅरियर की कई राहें खोलता जाता है। बारहवीं तक मैथ्स की पढ़ाई करने वालों के लिए सबसे खास बात है कि उन्हें अपने कॅरियर के विकल्प का चयन करते हुए किसी स्ट्रीम विशेष तक सीमित रहने की जरूरत नहीं होती। उनके लिए इंजीनियरिंग से लेकर रिसर्च तक, बैंक से लेकर स्टैटेस्टिक्स एनालिसिस तक और कोचिंग से लेकर स्कूल-कॉलेज में टीचिंग तक के सारे विकल्प खुल जाते हैं। मैथ्स की मदद से वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सिक्का जमा लेते हैं।

इंजीनियरिंग की राह

बारहवीं में साइंस के साथ मैथ्स लेने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स का लक्ष्य इंजीनियरिंग में जाना होता है। इंजीनियरिंग की विभिन्न परीक्षाओं के जरिए अच्छे कॉलेजों में आवेदन किया जा सकता है। इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए प्रवेश न मिल पाने पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में भी इन स्टूडेंट्स के लिए अवसर मौजूद हैं। इंजीनियरिंग के बाद अच्छे कॅरियर के कई मौके हैं।

परीक्षा में फायदा

मैथ्स की पढ़ाई करने वालों को प्रतियोगी परीक्षाओं में खास फायदा रहता है। मैथ्स के स्टूडेंटा होने के कारण ये कैट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के डाटा इंटरप्रेटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे सेक्शनों को आसानी से हल कर लेते हैं। इसके अलावा बैंक, यूपीएससी, एएससी आदि की परीक्षाओं में भी अपनी न्यूमेरिकल और रीजनिंग कमांड के दम पर ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

एवरग्रीन टीचिंग

मैथ्स को समझना फिर भी आसान है लेकिन यदि आप इस सब्जेक्ट को रूचिपूर्ण तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं तो मैथ्स टीचर के रूप में आपके पास कई विकल्प हैं। आप मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करके स्कूल में पढ़ा सकते हैं। नेट क्लीयर करने के बाद आप कॉलेजों में भी पढ़ा सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

सतीश शर्मा का जीएमसी ऊधमपुर दौरा, आपातकालीन सेवाओं में न हो कोई कोताही

ऊधमपुर 20 अप्रैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सतीश शर्मा ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) ऊधमपुर का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करना और ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संस्थान की समग्र तैयारियों का आकलन करना था। सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक खचाखच भरी यात्री बस पहाड़ी से करीब 100 मीटर नीचे गिर गई, जिससे कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 51 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस ने एक ऑटो-रिक्शा को कुचल दिया और फिर नीचे सड़क पर पलट गई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे रामनगर क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में स्थित कागोर्त गांव के पास एक खतरनाक मोड़ पर निजी बस के चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद पहाड़ी से गुजर रहे सेना के काफिले ने बचाव अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि बस में महिलाओं और छात्रों सहित 65 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश रामनगर से उधमपुर जाने वाले दैनिक यात्री थे। बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ क्योंकि बस लोहे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी और उसका ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। दौरे के दौरान, मंत्री ने आपातकालीन और ट्रॉमा सेक्शन सहित विभिन्न वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने घायलों को दिए जा रहे उपचार का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की और अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर उनका फीडबैक लिया। शर्मा ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर (गंभीर देखभाल बुनियादी ढांचा), दवाओं और नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी आपात स्थितियों के दौरान समय पर और कुशल चिकित्सा हस्तक्षेप कीमती मानव जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण है।

रॉयल लीजेंड क्लब ने 15.1 ओवर में हासिल की आसान जीत

जम्मू, 20 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू में आयोजित दूसरे शेर-ए-कश्मीर डे एंड नाइट टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के 9वें मुकाबले में रॉयल लीजेंड क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन क्रिकेट क्लब को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया। फ्रसे नो टू ड्रग्सफ्र अभियान के तहत आयोजित इस टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियन क्लब 133 रन पर सिमट गया, जिसमें सुनील कुमार ने 42 रन बनाए। जवाब में रॉयल लीजेंड क्लब ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 15.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य ने 45 रनों की तेज पारी खेली, जबकि एजी 37 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में अंचल सिंह ने 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री भाऊ रामपाल और विशेष अतिथि महेंद्र सिंह मौजूद रहे

मासूम की मौत पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

जम्मू,, 20 अप्रैल (हि.स.)। किश्तवाड़ में चार महीने के मासूम की दर्दनाक मौत के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना मुगल मैदान के राहलथल पंचायत में सामने आई जहां अस्थायी लकड़ी के पुल से नाला पार करते समय महिला, उसकी बहन और शिशु पानी में गिर गए। स्थानीय लोगों ने महिला और उसकी बहन को बचा लिया, लेकिन मासूम उस्मान अहमद का शव करीब 2 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। इस हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्थायी पुल निर्माण, पीड़ित परिवार को मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि पिछले साल पुल बह जाने के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया, जिससे यह हादसा हुआ। चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

बिश्नाह के युवक ने बाइक इंजन से बनाई पीयूबीजी बग्गी गाड़ी

जम्मू,, 20 अप्रैल (हि.सं.)। जम्मू के बिश्नाह के हरसा डब्ड गांव के रहने वाले मोहित कुमार ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए मोटरसाइकिल के इंजन और अन्य सामान से पीयूबीजी की मशहूर बग्गी गाड़ी तैयार कर दी है। इससे पहले भी मोहित ट्रैक्टर बना चुके हैं, जिससे उनकी तकनीकी क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोहित ने सरकार से अपील की है कि उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर ऐसे रचनात्मक और तकनीकी कार्यों में आगे आने की अपील की है।

जोड़ियां में क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए नशा मुक्त अभियान को बढ़ावा

जम्मू,, 20 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू के जोड़ियां में नशा मुक्त अभियान के तहत क्रिकेट मैदान से जागरूकता का संदेश दिया गया। समाजसेवी योगेश चौधरी द्वारा सेना के गड़ी ग्राउंड में मास्टर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जोड़ियां पुलिस और सेना का सहयोग रहा। यह आयोजन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर पुलिस के नशा मुक्त अभियान को ध्यान में रखते हुए किया गया। फाइनल मुकाबले में बकौर टीम ने डोंचक को हराते हुए जीत हासिल की, जिसमें कप्तान सुरिंदर ने शानदार नाबाद 103 रन बनाए। इस मौके पर कर्नल जे.एस. शाई और चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों को अपनाने की अपील की। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

जीएमसी अनंतनाग में युवक की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए

जम्मू,, 20 अप्रैल (हि.स.)। जीएमसी अनंतनाग में एक युवक की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि मरीजों की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री गुरु रविदास सभा ने मनाया 649वां प्रकाश उत्सव और डॉ. अंबेडकर की 135वीं जयंती

जम्मू, 20 अप्रैल। श्री गुरु रविदास सभा खौर ने श्री गुरु रविदास जी महाराज का 649वां प्रकाश उत्सव और भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती विक्रम सिंह की अध्यक्षता में मनाई। श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज ने शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया। उन्होंने कहा, माधो अविध्या हित कीन विवेक दीप मलीन, अर्थात शिक्षा के बिना विवेक समाप्त हो जाता है। नशा मुक्ति पर बोलते हुए उन्होंने कहा, रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतर जाए, नाम महा रस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर के जीवन और मिशन पर भी प्रकाश डाला और समानता के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज ने गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज खौर परिसर में फुले-शाहू-अंबेडकर लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में दर्शन लाओच, वित्त निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

टेक सक्षम के जरिए पारदर्शी और सुदृढ़ शासन का आगाज़

जम्मू 20 अप्रैल। कन्वेंशन सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ऐतिहासिक क्षमता-निर्माण कार्यशाला टेक सक्षम% की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर के डिजिटल भविष्य के लिए एक दृढ़ स्वर निर्धारित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल गवर्नेंस अब केवल एक सहायक कार्य नहीं रह गया है, बल्कि पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र की पूर्ण आधारशिला है। कार्यशाला में जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त शांतमनु; प्रमुख सचिव, गृह विभाग चंद्रकर भारती; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला; और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिमा मदान ने भी भाग लिया।

माजिद की हैट्रिक हीरोइक्स ने सबका दिल जीता, पांच विकेट से shine star की बड़ी जीत

जम्मू, 20 अप्रैल। एक रोमांचक मुकाबले में shine star क्रिकेट क्लब ने राजौरी titans पर शानदार जीत दर्ज की। यह मैच vs जम्बू लोचन t20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मौलाना आजाद स्टेडियम में खेला गया, जिसका आयोजन जम्मू एंड कश्मीर मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। टॉस जीतकर shine star ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए। वरुण कुमार ने 23 गेंदों पर 46 रन की तेज पारी खेली, जिसमें चार छक्के और तीन चौके शामिल थे। माजिद हुसैन ने 32 गेंदों पर 40 रन बनाए, जबकि निशांत कुमार ने 15 गेंदों में 23 रन जोड़े। रफीक ने भी 18 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। राजौरी titans की ओर से इमरान, मुकेश और फैजल देव ने दो-दो विकेट लिए, जबकि शाहिद और उमेश को एक-एक विकेट मिला। जवाब में राजौरी titans की टीम दबाव में आ गई और 10.3 ओवर में सिर्फ 68 रन पर ऑल आउट हो गई। shine star की गेंदबाजी बेहद प्रभावशाली रही। माजिद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट लिए और टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी अपने नाम की। अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए माजिद हुसैन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यह पुरस्कार प्रवाल शर्मा, हैंडबॉल राष्ट्रीय खिलाड़ी और j&k पिकलबॉल एसोसिएशन के महासचिव, तथा श्री दयाल सिंह (sgct), वेटलिफ्टिंग कोच j&k पुलिस द्वारा प्रदान किया गया।

बारामूला में इंटर-स्कूल प्रतियोगिताओं में शतरंज और इंडोर खेलों का उत्साह

बारामूला, 20 अप्रैल। जिला युवा सेवा एवं खेल (dyss) बारामूला द्वारा आयोजित इंटर-स्कूल जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी लगातार देखने को मिल रही है। ये प्रतियोगिताएं वार्षिक खेल कैलेंडर के तहत जिले के विभिन्न जोनों में आयोजित की जा रही हैं। ये प्रतियोगिताएं जोन डांगीवाचा, डेंजरपोरा, चंदनवाड़ी, सिंगपोरा पत्तन और कुंजर में सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं, जिनमें सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र-छात्राएं सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जोन डांगीवाचा में अंडर-14 और अंडर-17 बालिकाओं के लिए शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 43 छात्राओं ने भाग लेकर अपनी रणनीतिक सोच और कौशल का प्रदर्शन किया। इसी तरह, जोन डेंजरपोरा में अंडर-14 बालिकाओं के लिए शतरंज प्रतियोगिता के दूसरे दिन 34 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

NOTICE

I, Parsenoo Devi w/o sanatan Kumar R/o kanehri Tehsil chowki choura and District jammu have applied for correction of my name Parsenoo Devi which has been wrongly written as parsino Devi and instead of correct name Parsenoo Devi in my Aadhar card bearing No 6945 7204 1690 objection if any may be conveyed to the concerned authority within seven days from the date of publication of this notice.

स्मार्ट सिटी बस सेवाओं के प्रस्तावित विस्तार के खिलाफ कश्मीर में हड़ताल, दैनिक जीवन और यातायात बाधित

श्रीनगर, 20 अप्रैल (हि.स.)। श्रीनगर सहित कश्मीर के जयदातार हिस्सों में सोमवार को दैनिक जीवन और यातायात बाधित हो गया क्योंकि परिवहनकर्ताओं ने जिला मार्गों पर स्मार्ट सिटी बस सेवाओं के प्रस्तावित विस्तार के खिलाफ हड़ताल की।

विरोध प्रदर्शन में बस, सुमो और तावेरा चालकों सहित निजी परिवहन संचालक सड़कों से दूर रहे जबकि घाटी के विभिन्न बस अड्डों पर धरना दिया गया।

यह आंदोलन परिवहन समुदाय के भीतर उनकी आजीविका पर स्मार्ट सिटी बस विस्तार के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। प्रदर्शनकारी संचालकों ने कहा कि जिला मार्गों पर सरकार समर्थित बस सेवाओं के विस्तार से निजी परिवहन पर निर्भर हजारों परिवारों की आय को खतरा हो सकता है।

उन्होंने मांग की कि सरकार अनिश्चितता और निजी ऑपरेटरों के लिए व्यवसाय के संभावित नुकसान का हवाला देते हुए निर्णय को वापस ले। हड़ताल के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं लेकिन निजी वाहन सामान्य रूप से चलते रहे जि से शहर में समग्र व्यवधान सीमित हो गया।स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण रही, विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों तक ही सीमित रहे और कानून-व्यवस्था के बड़े मुद्दों की कोई सूचना नहीं है।

डीएस ग्रुप ने कैच प्रीमियम आयोडाइज्ड पिंक रॉक सॉल्ट के लिए अपना पहला टीवीसी लॉन्च किया

नई दिल्ली, 20 अप्रैल। कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेज, अग्रणी एफएमसीजी समूह और मल्टी बिजनेस कारपोरेशन धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप (डीएस ग्रुप) का एक लोकप्रिय ब्रांड है। कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेज ने अपने कैच प्रीमियम आयोडाइज्ड पिंक रॉक सॉल्ट के लिए पहली बार एक टीवी विज्ञापन (टीवीसी) लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह विज्ञापन डेंट्सू क्रिएटिव वेबचटनी ने बनाया है। इस कैंपेन के जरिए डीएस ग्रुप अब मसालों और स्प्रिंकलर्स से आगे बढ़कर नमक कैटेगरी में भी अपनी बात रख रहा है। इस टीवीसी का मकसद लोगों को डीएस ग्रुप के नमक के बारे में जागरूक करना है। यह टीवी, सोशल मीडिया और ओटीटी पर दिखाया जाएगा।

विज्ञापन में एक मोहल्ले के पार्क जैसी जगह का मज़ेदार और आम दिनचर्या का सीन दिखता है, जहाँ दो मॉएँ और उनके बच्चे बातें कर रहे होते हैं। कहानी के बीच में एक छोटी लड़की बड़े ही भोलेपन से कैच प्रीमियम पिंक रॉक सॉल्ट के फायदे और इसके आने की कहानी समझाती है।

अर्नब घटक चौधरी, जनरल मैनेजर (मार्केटिंग), कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस ने कहा, फ्रइस कैंपेन के जरिए हमने नमक के फायदों को एक आम रोज़मर्रा के सीन में पेश करने की कोशिश की है। विज्ञापन में दो पड़ोसियों के बीच होती बातचीत के जरिए हमने कैच पिंक रॉक सॉल्ट की खासियतों को दिखाया है। यह कैंपेन हमारी सोच 'क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता को और मजबूत करता है।'

सुरजो दत्त, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर - डेंट्सू क्रिएटिव वेबचटनी ने कहा, हम चाहते थे कि नमक को सिर्फ एक रसोई का ज़रूरी सामान न समझा जाए, बल्कि एक समझदारी भरी चीज़ के तौर पर देखा जाए। बच्चों को कहानी के केंद्र में रखकर हमने यह दिखाया है कि आज के घरों में जागरूकता बढ़ी है। विज्ञापन इसी बात पर खत्म होता है कि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि यह हमारे अच्छे चुनावों का प्रतिबिंब होता है।

कैथ लैब और अन्य सुविधाओं से दक्षिण कश्मीर और चेनाब वैली के मरीजों को नई उम्मीद

जम्मू, 20 अप्रैल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग तेजी से उन्नत हृदय देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है, जिससे दक्षिण कश्मीर और चेनाब वैली के कई हिस्सों के मरीजों को नई उम्मीद मिली है। संस्थान में अत्याधुनिक कैथ लैब की स्थापना क्षेत्र में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अप्रैल 2025 में शुरू की गई इस हाई-टेक कैथ लैब ने दक्षिण कश्मीर में कार्डियक केयर की तस्वीर बदल दी है। महज 9 महीनों में कार्डियोलॉजी विभाग ने 3000 से अधिक प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा जीवन रक्षक हस्तक्षेप जैसे प्राथमिक एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर प्रत्यारोपण शामिल हैं। यह कैथ लैब कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर प्रत्यारोपण, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी और अन्य उन्नत प्रक्रियाओं को समय पर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे मरीजों को अब विशेष इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। डॉ. सैयद मकबूल के नेतृत्व में, और विशेषज्ञों जैसे डॉ. शमीम इकबाल, डॉ. शौकत हुसैन शाह और डॉ. शाहूद की टीम प्रतिदिन औसतन 10-15 प्रक्रियाएं कर रही है। यह सुविधा दक्षिण कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग के कई जिलों जैसे बनिहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के मरीजों को भी सेवा दे रही है। कार्डियोलॉजी विभाग ने आपातकालीन सेवाओं में भी उच्च दक्षता दिखाई है, जहां 12 घंटे के भीतर 8 मामलों में केवल 15-20 मिनट का डोर-टू-बैलून समय हासिल किया गया, जो उच्च चिकित्सा मानकों का संकेत है।

Department of Wildlife Protection Office of the Regional Wildlife Warden Jammu

N O T I F I C A T I O N

Subject: Updated Tentative Seniority List of Senior Assistants and Junior Assistantsof Wildlife Region Jammu.

Whereas a Final/Updated Seniority List of Senior Assistants and Junior Assistantsof Wildlife Protection Department of Jammu Region as it stood on 31-07-2025 was issued vide thisOffice No.RWLWJ/2025-26/2910-20 dated11-09-2025.

Whereas, it has become imperative to update and notify the Seniority list of Senior Assistants and Junior Assistantsby inserting/deleting the names of those who were promoted to the next higher grade.

Now, therefore, an updated tentative seniority list of Senior Assistants and Junior Assistants as it stood on 01-04-2026 forming Annexure "A" to this notification is hereby issued for information of all the concerned official of this department.

Anyofficial having objections with regard to his placement in the updated tentative seniority list shall represent before this office alongwith all relevant/supporting documents within 15 days through proper channel from the date of issuance of this notification, failing which it shall be presumed that there is no objection from any official against his placement in the updated tentative seniority list and the final seniority list shall be issued accordingly.

The date of birth(s) recorded against the officials are provisional and subject to verification with the original Matriculation certificate/service book.

No: RWLWJ/2026-27/ Dated: 04-2026

DIP/J-796/26
Dtd: 20-4-2026

Sd/-
Dr. V.S. Senthil Kumar IFS
Regional Wildlife Warden
Jammu.

Annexure "A"

Updated TentativeSeniority List of "Senior Assistants" working in Wildlife Region Jammu as it stood on 01-04-2026

Annexure "A"

Updated TentativeSeniority List of *"Senior Assistants"* working in Wildlife Region Jammu as it stood on 01-04-2026

Seniority position	Name of the Official	Qualification	Date of Birth	Date of Appointment	Date of promotion	Category if any	Present place of posting
01	Sh. Sudesh Koul	B.Sc	02-03-1967	09-09-1992	30-09-2021	General	Regional Office Jammu
02	Sh. Vishal Choudhary	MA	15-02-1988	15-09-2018	27-03-2026	General	Regional Office Jammu

Updated TentativeSeniority List of Junior Assistants working in Wildlife Region Jammu as it stood on 01-04-2026

Seniority position	Name of the Official	Qualification	Date of Birth	Date of Appointment	Date of promotion	Category if any	Present place of posting
01	Sh. Bipen Kumar Gupta	(10+2)	01.09.1966	02.02.2000	17-06-2020	General	Regional Office Jammu
02	Sh. Vijay Singh	Matric	26.09.1978	19.12.2007	30-09-2021	General	Regional Office Jammu
03	Sh. Arun Kumar	B.Sc	28-03-1989	25-10-2019	27-03-2026	General	Regional Office Jammu

संपादकीय

आने वाले दिन हो सकते हैं चुनौतीपूर्ण

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने के प्रभाव अब पूरे देश में दिखने लगे हैं। एक बार फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल और वाणिज्यिक एलपीजी के दामों में काफी वृद्धि हुई है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो अस्त्र की कीमत बढ़कर रिकॉर्ड 2.07 लाख रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है, हालांकि घरेलू एयरलाइंस के लिए यह वृद्धि केवल 8.5 प्रतिशत ही होगी। वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 195.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। यह पहली बार है जब ATF की कीमत 2 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के आंकड़े को पार कर गई है।

सरकार ने आम लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू एयरलाइंस के लिए कीमतों में कुछ हद तक संतुलन बनाया है। यह उल्लेखनीय है कि 1 मार्च को ATF की कीमत में 5.7 प्रतिशत (5244.75 रुपये प्रति किलोलीटर) की बढ़ोतरी की गई थी।

इस वृद्धि का असर बढ़ता ही जाएगा, जिससे एयरलाइंस को यह अतिरिक्त बोझ यात्रियों पर डालना पड़ेगा। 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 1 मार्च को 114.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि घरेलू एलपीजी की कीमत 7 मार्च को 14.2 किलो सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़ाई गई थी।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि लोग कठिन समय के लिए तैयार रहें, क्योंकि हालात में सुधार की उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आती है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से उत्पन्न संकट के बीच सावधानीपूर्वक कदम उठा रही है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं। इस तरह के संकट का प्रभाव केवल ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन लागत, आपूर्ति श्रृंखला और अंततः आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से महंगाई का दबाव बढ़ता है, जिससे घरों, छोटे व्यवसायों और उद्योगों पर असर पड़ता है। हवाई किराए में वृद्धि से लेकर लॉजिस्टिक्स खर्च तक, इसका बोझ पूरे आर्थिक तंत्र पर महसूस किया जाएगा, जिससे संतुलित और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह जरूरी है कि लोग जिम्मेदारी से व्यवहार करें और स्थिति की गंभीरता को समझें। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों ने भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, इसलिए भारत के लोगों को भी स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। इस समय लोगों को अफवाहों पर विश्वास करने, घबराहट में खरीदारी करने और अपुष्ट जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। अंततः, सभी को संयम और सामूहिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इन कठिन परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए।

कचरा प्रबंधन और भारत के प्रयास

कुलभूषण उपमन्यु

विश्व की पर्यावरणीय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कचरे के कारण बड़ी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। न केवल मनुष्य समाज बल्कि समस्त जीव-जगत और वनस्पतियां भी कचरा जनित प्रदूषण का दंश झेलने को अभीशप्त हैं। हवा, पानी और जमीन सब इस प्रदूषण की चपेट में है।

इससे वनस्पति और सारा जीव-जगत बीमारियों और जीवन संकट से गुजर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और वैश्विक नागरिक अपशिष्ट में भारत की हिस्सेदारी 12 फीसद है। भारत प्रतिवर्ष 620 लाख टन कचरा पैदा करता है।

इसमें से केवल 430 लाख टन ही एकत्रित होता है और 120 लाख टन ही उपचारित होता है। 310 लाख टन लैंड फिल में डाल दिया जाता है। शेष यहां-वहां पड़ा रहता है और जंगलों, ढलानों, खेतों, जल संसाधनों को प्रदूषित करता रहता है। उसमें से कुछ खुले में जलाया जाता है। यहविषैली गैसों को स्थानीय स्तर पर फैला कर गंभीर बीमारियों का कारण बनता है।

हालांकि सरकार इसके लिए समय-समय पर नियम बनाती है। इनके खराब क्रियान्वयन के चलते स्थिति में कोई सुधार आता दिखाई नहीं देता है। गरीब बस्तियों के नजदीक डंपिंग, प्रबंधन और लापरवाही से संबंधी डेटा के अभाव के चलते नीति निर्माण और क्रियान्वयन में बाधा होती है। उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 सख्ती से लागू किए जाएं और लापरवाही करने वालों को दंडित करने के भी प्रावधान किए गए। मुख्य निर्देश निम्न हैं- ठोस कचरा चार भागों में अलग करके एकत्र किया जाए। 1. गीला कचरा, जिसमें रसोई अपशिष्ट, भोजन,फल,सब्जियां आदि शामिल हैं। 2. सूखा कचरा, जिसमें प्लास्टिक,कागज़, धातु, कांच शामिल हैं।

3. सैनिटरी, नैपकिन, डायपर आदि के अलग अलग निपटारे की व्यवस्था करनी होगी। 4. विशेष, श्रेणी में बल्ब, बैटरी, दवाइयां आदि के लिए विशेष अधिकृत इकाइयों को ही संशोधित करने के लिए देना होगा। गीले कचरे से मीथेन बना कर ईंधन के लिए प्रयोग करना। खास कर 100 किलो दैनिक सूखा अपशिष्ट, 40,000 लीटर दैनिक पानी उपयोग करने वाली और 20,000 वर्ग मीटर में फैली इकाइयां थोक अपशिष्ट उत्पादक घोषित की गई हैं, जिन्हें गीला कचरा अपने परिसर में ही प्रसंस्कृत करना पड़ेगा।

सूखा कचरा रिकवरी फैसिलिटी को पुनः चक्रीकरण के लिए देना होगा। सूखे कचरे में से जिसका पुनः चक्रीकरण संभव नहीं होगा उसके पेलेट्स बना कर सीमेंट प्लांट और उर्जा उत्पादक इकाइयों को ईंधन के रूप में देना होगा, जिसकी मात्रा 5 फीसद से बढ़ा कर 15 फीसद की गई है। किसी भी तरह के पुन-चक्रीकरण या उपयोग के योग्य कचरे को ही लैंड फिल में डालने की अनुमति होगी। आम कचरा वहां डालने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पुराने संचित अपशिष्ट को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए योजना बनानी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे स्थानीय निकायों के माध्यम से पर्यटक शुल्क लगा सकते हैं और पर्यटक संख्या नियंत्रित कर सकते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम बनाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व निगरानी समितियों के माध्यम से नियम लागू किए जाएंगे। एक केंद्रीकृत पोर्टल कचरा उत्पादन, संग्रह,और निपटारे की निगरानी करेगा और भौतिक सूचनाओं को डिजिटल ऑडिट में बदलेगा। प्रबंधन के लिए अपशिष्ट से धन और उर्जा के रास्ते पर काम हो रहा है। प्लास्टिक कचरे का अलग से प्रसंस्करण करना और प्रोजेक्ट री प्लान के तहत कैरी बैग निर्माण में 20 फीसद कपास के रेशे मिलाने की योजना है।

पैकिंग सामग्री के निर्माताओं, आयातकों, और खुदरा विक्रेताओं की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। स्थानीय स्वशासन के सभी निकायों नगर निकायों और पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों, मेयर और काउंसल विशेष रूप से नियमों को लागू करने और जागरुकता फ़ैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। नियमों को लागू करने में विफलता या ढील के चलते इन चुने हुए स्थानीय स्वशासन के जिम्मेदार लोगों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। कचरा पैदा करने वाले और प्रबंधन की जिम्मेदारी में ढील बरतने वाले, दोनों को ही दंड के दायरे में रखा गया है। यह नियम पहली अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। किन्तु मुख्य चुनौती तो इन प्रावधानों को सही से लागू करने करवाने की है। कचरा प्रबंधन नियम तो 2016 से ही लागू हो गए हैं। वर्तमान में उनको अधिक सख्त बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है। फिर भी जब तक गंभीरता पूर्वक लागू करने की व्यवस्था खड़ी नहीं की जाती, समस्या बनी ही रहेगी। जागरुकता इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।

हर नागरिक को लगना चाहिए कि वह इन नियमों का पालन करके अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है। पर्यावरण की रक्षा कोई दया परोपकार का काम नहीं है बल्कि अपने ही वर्तमान और दीर्घकालीन जीवन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने का काम है। इसके लिए विकेन्द्रित प्रबन्धन प्रणालियां बना कर

कचरा पैदा करने वाले और प्रबंधन की जिम्मेदारी में ढील बरतने वाले, दोनों को ही दंड के दायरे में रखा गया है। यह नियम पहली अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। किन्तु मुख्य चुनौती तो इन प्रावधानों को सही से लागू करने करवाने की है। कचरा प्रबंधन नियम तो 2016 से ही लागू हो गए हैं। वर्तमान में उनको अधिक सख्त बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है।

पंचायत स्तर तक व्यवस्था खड़ी करनी होगी। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान और व्यवहारिक पुनः चक्रीकरण कार्यक्रमों के द्वारा जागरुकता फैलाई जानी चाहिए होगी। वरना यह कचरा समुद्री जीवों के विनाश से ले कर जमीन की उपजाऊ शक्ति का ह्रास और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से जीवन को अधिकाधिक कठिन और रोगी बनाता जाएगा। सचेत होने का समय है, क्योंकि औद्योगिक स्वार्थ और हमारी लापरवाही जीव जगत पर भारी पड़ने वाली है।

(लेखक, हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष और पर्यावरणविद् हैं।)

सत्ता में महिलाओं की भागीदारी, आठ देश सबसे आगे

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

संसद में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का विधेयक गिरने के साथ ही देश में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से महिलाओं से माफी मांगी है तो दूसरी और विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत और सरकार की हार बताई है। हालांकि विपक्ष यह भी कह रहा है कि उनका विरोध सीटों के परिसीमन से अधिक है। खैर, यह अलग बहस का विषय हो सकता है।

पर एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में हम दुनिया के देशों से अभी काफी पीछे चल रहे हैं। दुनिया के 190 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हमारे देश का स्थान 147 वां आता है। दुनिया के देशों में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक स्तर औसत 27.5 फीसदी है। 30 राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं है तो दुनिया के केवल आठ देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं वहीं इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार हालिया चुनाव में 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 19 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर चुनाव घोषणा पत्र बनाये और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की।

बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों में लखपति दीदी या इसी तरह के नाम से मिलती जुलती योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने की रणनीति महिला वोटों को अपनी और करने की रही है, यह दूसरी बात है कि इसका लाभ किस पार्टी को अधिक मिला। एक बात साफ हो जानी चाहिए राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक बढ़ नहीं पाई है।

महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 प्रतिशत है वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। रोचक बात यह है कि 2009 की 15 वीं लोकसभा के पहले तक तो हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचा था। 15 वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। हालांकि 1977 में आपातकाल के ठीक बाद की लोकसभा में सबसे कम भागीदारी केवल 3.5 प्रतिशत ही रह गई थी। पर 1977 के हालात अलग थे और उनको अलग करके देखा जाना चाहिए। उस समय आपातकाल के बाद की स्थितियां थीं। 18 वीं लोकसभा में 17 वीं लोकसभा की तुलना में 3 महिला सांसद कम है। इस तरह से 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही।

जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो भले ही महिला आरक्षण बिल का अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस व अन्य विपक्षियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष में मतदान किया पर लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी की महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस की भागीदारी 14.3 प्रतिशत और बीजेपी की भागीदारी 12.9 प्रतिशत है। अन्य दलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है तो इस समय देश में सर्वाधिक महिला सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ में कुल सदस्यों में 21.1 प्रतिशत महिला सदस्य है। त्रिपुरा में 15 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। बाकी देश के अन्य राज्यों में 15 प्रतिशत महिलाएं भी विधानसभा की सदस्य नहीं है। नागालैंड देश का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कम महिला सदस्य हैं। कर्नाटक जैसे राज्य में भी पांच प्रतिशत से कम महिला विधानसभा सदस्य हैं।

खैर इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं है। जहां महिलाओं की सीटे आरक्षित होने से आज तस्वीर ही बदल गई है। आज सरपंच पति या प्रधान

जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो भले ही महिला आरक्षण बिल का अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस व अन्य विपक्षियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष में मतदान किया पर लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी की महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस की भागीदारी 14.3 प्रतिशत और बीजेपी की भागीदारी 12.9 प्रतिशत है। अन्य दलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है तो इस समय देश में सर्वाधिक महिला सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ में कुल सदस्यों में 21.1 प्रतिशत महिला सदस्य है।

पति वाली बात भी नहीं रही है। पिछले चुनाव परिणाम भी यह साफ कर चुके हैं कि आज महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। यही कारण है कि सरकार बनने और बनाने में महिलाओं मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। आने वाले समय में इसमें और अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में एक बात साफ हो जानी चाहिए कि बिना आरक्षित सीटों के विधानसभाओं या संसद में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी बढ़ने की कल्पना करना बेमानी होगी। यह तो संवैधानिक बाध्यता से ही संभव हो पाएगा। यह सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा। यदि महिलाओं की सत्ता में सहभागिता बढ़ानी है तो महिला सीटों का आरक्षण करना ही होगा। यह अवश्य है कि आरक्षण की सीमा आपसी समन्वय व विचार-विमर्श से सर्वसम्मति से तय होता है तो यह बेहतर लोकतांत्रिक परंपरा होगी। राजनीतिक दलों को आपसी आग्रह दुराग्रहों से हटकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गैरसरकारी संगठनों को भी इस दिशा में देश में माहौल बनाना चाहिए। यह साफ है कि अब समय आ गया है जब महिलाओं की हिस्सेदारी तय होनी ही चाहिए।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पेयजल का बढ़ता कारोबार- संकट, लापरवाही और भविष्य की चेतावनी

– डॉ. लक्ष्मीनारायण वैष्णव

एक दिन पानी भी बिकेगा—कभी यह वाक्य सुनकर लोग मुस्कुरा देते थे, लेकिन आज यह हमारे समय की सबसे कड़वी सच्चाई बन चुका है। जिस जल को प्रकृति ने मानव जीवन के लिए सहज और निःशुल्क उपलब्ध कराया था, वही आज बाजार की वस्तु बन गया है। घरों के बजट में अब पानी भी एक आवश्यक खर्च बन चुका है। यह केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक, पर्यावरणीय और नीतिगत संकट का स्पष्ट संकेत है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और नीतिगत विफलता

यदि हम स्वतंत्रता के बाद के भारत पर दृष्टि डालें, तो जल उपलब्धता में आई गिरावट चिंता का विषय है। वर्ष 1947 में प्रति व्यक्ति लगभग 6042 क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध था, जो समय के साथ घटकर 2001 में 1816, 2011 में 1545 और 2016 तक लगभग 1495 क्यूबिक मीटर रह गया। यह गिरावट केवल प्राकृतिक कारणों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी नीतिगत लापरवाही और संसाधनों के अनुचित प्रबंधन का दुष्परिणाम है।

भारतीय संविधान नागरिकों को जीवन का अधिकार देता है, जिसमें स्वच्छ पेयजल भी एक अनिवार्य तत्व है। किंतु आज की वास्तविकता यह है कि नागरिकों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। जिन पूर्वजों ने कुएं, बावड़ियां, तालाब और प्याऊ बनाकर समाज को जल समृद्ध बनाया, उनके वंशज आज बोतलबंद पानी पर निर्भर हो गए हैं, यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति है।

वर्तमान जल संकट - कारण और परिणाम

आज भारत जल संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और भूजल का अंधाधुंध दोहन इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। नदियां सिकुड़ रही हैं, भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और पारंपरिक जल स्रोत उपेक्षा के कारण समाप्त होते जा रहे हैं।

देश में होने वाली वर्षा का लगभग 65 प्रतिशत जल बिना संग्रहण के समुद्र में चला जाता है। यदि इस जल का समुचित संचयन किया जाए, तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। किंतु इस दिशा में ठोस और दीर्घकालिक प्रयासों का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

जलवायु परिवर्तन और असंतुलन

जल संकट अब केवल संसाधन प्रबंधन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन से भी गहराई से जुड़ चुका है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी चरम स्थितियां देखने को मिल रही हैं। वर्षा का असंतुलन कृषि, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन तीनों को प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत देती है।

पानी का व्यवसाय मजबूरी से मुनाफा

पेयजल संकट ने एक विशाल बाजार को जन्म दिया है। बोतलबंद पानी, आरओ सिस्टम और टैंकर सप्लाई का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। यह विडंबना ही है कि जो जल जीवन का आधार है, वही आज लाभ कमाने का साधन बन गया है। एक ओर व्यवसायी इस संकट से लाभ कमा रहे हैं, वहीं आम नागरिक के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनता जा रहा है।

इसके साथ ही दूषित जल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे चिकित्सा खर्च भी बढ़ रहा है। इस प्रकार जल संकट अब सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता को भी बढ़ावा दे रहा है।

सरकारी पहल और चुनौतियां

जल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन तथा अटल भूजल योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना और भूजल स्तर को सुधारना है।हालांकि इन योजनाओं की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

जब तक प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनसहभागिता का समुचित समन्वय नहीं होगा, तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना कठिन रहेगा।

समाधान की दिशा- परंपरा और तकनीक का समन्वय

भारत की पारंपरिक जल संरचनाएं—कुएं, तालाब, बावड़ियां—आज भी हमें जल संरक्षण का मार्ग दिखाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन पारंपरिक उपायों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, भूजल दोहन पर नियंत्रण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता, ये सभी कदम अत्यंत आवश्यक हैं।

इसके साथ ही कृषि और शहरी क्षेत्रों में जल के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इससे जुड़े तथ्य आज यही कहते हैं कि यदि वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो वर्ष 2050 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे जा सकती है, जो गंभीर जल संकट की स्थिति होगी।अतः यह समय चेतने का है। पानी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसका संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि आज हमने जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा।

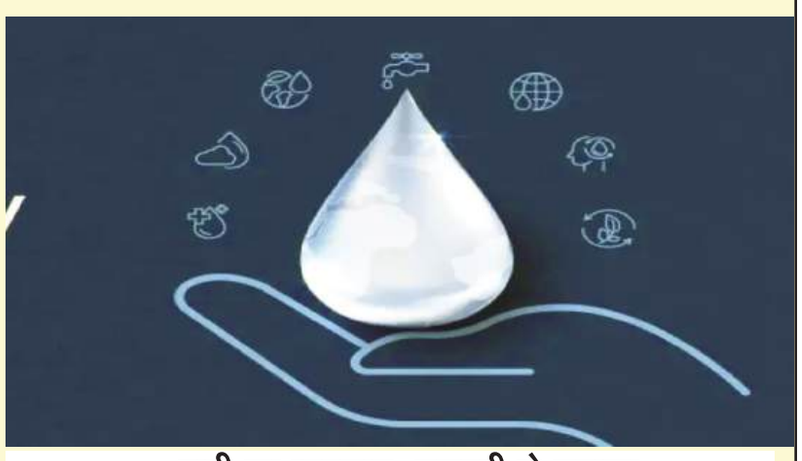

पानी का व्यवसाय मजबूरी से मुनाफा

पेयजल संकट ने एक विशाल बाजार को जन्म दिया है। बोतलबंद पानी, आरओ सिस्टम और टैंकर सप्लाई का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। यह विडंबना ही है कि जो जल जीवन का आधार है, वही आज लाभ कमाने का साधन बन गया है। एक ओर व्यवसायी इस संकट से लाभ कमा रहे हैं, वहीं आम नागरिक के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनता जा रहा है इसके साथ ही दूषित जल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे चिकित्सा खर्च भी बढ़ रहा है। इस प्रकार जल संकट अब सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता को भी बढ़ावा दे रहा है।

मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 2-1 से हराया, एवर्टन के खिलाफ लिवरपूल ने दर्ज की जीत

एजेंसी

लंदन । मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग में टॉप पर चल रही आर्सेनल को एतिहाद स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराया। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच सिर्फ 3 अंकों का फासला बचा है। मैनचेस्टर सिटी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। मैच की शुरुआत में मैनचेस्टर सिटी ने आक्रामक खेल दिखाया। 16वें मिनट में रेयान चेर्की ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। चेर्की ने दो डिफेंडरों को छकाते हुए और डेविड राया के पास से दाहिने पैर से शॉट मारकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। हालांकि, इसके तुरंत बाद आर्सेनल ने वापसी की। मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुम्मा की गलती का फायदा उठाकर काई हैवर्ट्ज ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। पहले हाफ में इसके बाद कोई और गोल नहीं हुआ और स्कोर 1-1 रहा। दूसरे हाफ में मैनचेस्टर सिटी ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। 65वें मिनट में एर्लिंग हालैंड ने सिटी के लिए मैच में दूसरा गोल किया और स्कोर को 2-1 कर दिया। इसके बाद आर्सेनल की तरफ से गोल करने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल सकी। मैनचेस्टर सिटी मुकाबले को 2-1 से अपने नाम करने में सफल रही।

दिव्या पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ फाइनल में रोमांचक मुकाबला, टीम विलेजिओ ने 1 रन से जीता खिताब

चंडीगढ़। दिव्या पब्लिक स्कूल में खेले गए फाइनल मुकाबले में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला, जहां टीम विलेजिओ ने चंडीगढ़ टाइगर्स को मात्र 1 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम विलेजिओ ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। टीम की ओर से अमन ने शानदार नाबाद 79 रनों की पारी खेली और अंत तक टिककर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। चेतन शर्मा ने 42 रन, आर्यन ने 28 रन और हरविंदर ने 25 रनों का योगदान दिया। चंडीगढ़ टाइगर्स की ओर से अभिषेक, चंदन और प्रियांशु ने 1-1 विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंडीगढ़ टाइगर्स की टीम ने भी शानदार संघर्ष किया, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 189 रन ही बना सकी और मुकाबला 1 रन से हार गई। टीम की ओर से कमल ने नाबाद 85 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि अभिषेक और चंदन ने 25-25 रन बनाए। गेंदबाजी में टीम विलेजिओ की ओर से अमित गांधी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके। वहीं हरविंदर नैन और अभिषेक ने 1-1 विकेट हासिल किया।

खराब फॉर्म से जूझ रहे मोहम्मद रिजवान को वापसी की उम्मीद, टी20 इंटरनेशल पर नजर

नई दिल्ली । खराब फॉर्म से जूझ रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की नजर क्रिकेट में वापसी पर है। उनका कहना है कि सभी फॉर्मेट में जगह बनाने की कोशिश है। 33 वर्षीय मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के लिए टेस्ट और एकदिवसीय के अहम खिलाड़ी हैं। वर्ष 2024 के आखिर से टी20 इंटरनेशनल टीम में नहीं हैं। इस साल की शुरुआत में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप टीम से भी बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। रावलपिंडी के लिए रिजवान सात पारियों में सिर्फ 107 रन ही बना पाए हैं, जिसमें 20 से कम के पांच स्कोर शामिल हैं। अपनी आलोचना और खराब प्रदर्शन को लेकर आईसीसी के हवाले से मोहम्मद रिजवान ने कहा कि खिलाड़ी भी इंसान होते हैं और अपने करियर में मुश्किल दौर से गुजरते हैं, और मेरे लिए भी यह अलग नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी सभी फॉर्मेट में क्रिकेट खेलना पसंद है, और मुझ पर हो रही आलोचना की वजह से मेरा खेल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि संन्यास लेने का विचार मन में नहीं है। मेरा मानना है कि एक खिलाड़ी को संन्यास के बारे में तभी सोचना चाहिए जब उसे पता हो कि वह दूसरों से मुकाबला करने की क्षमता खो चुका है और क्रिकेट में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई है। मैं अभी भी दूसरों से मुकाबला कर सकता हूं। बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी टीम में जगह बनाई। पाकिस्तान पांचवें स्थान पर है। इस साल के आखिर में इंग्लैंड का टेस्ट दौरा और 2027 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शामिल है।

दिल्ली के खिलाफ घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा हैदराबाद

हैदराबाद : पिछले दो मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दोनों टीम के अभी छह-छह अंक है लेकिन सनराइजर्स का नेट रन रेट बेहतर है और इसलिए वह चौथे स्थान पर काबिज है। कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में सनराइजर्स की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही थी लेकिन उसने धीरे-धीरे इसमें सुधार कर लिया है। कमिंस भी टीम से जुड़ गए हैं लेकिन वह इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। सनराइजर्स की तरफ से पिछले दो मैच में अपेक्षाकृत कम चर्चित खिलाड़ियों प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन और शिवांग कुमार ने मौकों का पूरा फायदा उठाया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हिंगे के शानदार प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ ईशान मलिंगा की अगुवाई में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।

आईपीएल 2026: कोनॉली ने की प्रियांश आर्य की तारीफ, कहा- 'हम एक-दूसरे से छोटी-छोटी चीजें सीखते हैं'

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के युवा ऑलराउंडर कूपर कोनॉली ने अपनी निरंतरता और समझदारी भरी बल्लेबाजी से खास पहचान बनाई है। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर महज 80 गेंदों में 182 रनों की बेहतरीन साझेदारी की, जो इस सीजन की सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से एक रही। मैच के बाद कोनॉली ने कहा कि वह और आर्य एक-दूसरे से लगातार सीख रहे हैं और अपने खेल को बेहतर बना रहे हैं। कोनॉली ने कहा, 'हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है। हम इस पर चर्चा करते हैं कि किसके लिए क्या बेहतर काम करता है और हम एक-दूसरे से छोटी-छोटी चीजें सीखते हैं। हमारा लक्ष्य लगातार बेहतर बनना और टीम

को आगे ले जाना है।' इस सीजन में कोनॉली ने अब तक 223 रन बनाए हैं, जो टीम के अन्य प्रमुख बल्लेबाजों प्रियांश आर्य (211), प्रभसिमरन सिंह (211) और श्रेयस अय्यर (208) से ज्यादा हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी ताकत के अनुसार खेलने और अनावश्यक जोखिम न लेने को दिया। उन्होंने कहा, 'हर खिलाड़ी को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और उसी पर टिके रहना चाहिए। विपक्षी टीम आपकी कमजोरी ढूंढती है, लेकिन जरूरी है कि आप उसे समझें और उस पर काम करें।' कोनॉली के प्रदर्शन में टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग की भूमिका भी अहम रही है। पोंटिंग के मार्गदर्शन में उन्हें अपने खेल को निखारने का मौका मिला है। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर की नेतृत्व क्षमता की भी उन्होंने सराहना की। कोनॉली ने कहा, 'पोंटिंग और श्रेयस की जोड़ी टीम को सही दिशा दे रही है। श्रेयस एक शानदार लीडर हैं, जो टीम को सहज माहौल देते हैं और हर खिलाड़ी को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं।' पंजाब किंग्स का मौजूदा प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है और खिलाड़ियों के बीच तालमेल मजबूत हो रहा है।

शेफाली वर्मा 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पांचवीं भारतीय महिला बनीं

एजेंसी

डरबन (दक्षिण अफ्रिका)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के बाद 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पांचवीं भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। शेफाली ने यह मुकाम दक्षिण अफ्रीका के विरूद्ध डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान हासिल किया। भारतीय टीम इस समय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां वह पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेल रही है। पहला मैच जीतकर मेजबान टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आई। टीम की सलामी शेफाली वर्मा जैसे ही मैदान पर कदम रखा, उन्होंने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने की उपलब्धि हासिल कर ली। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जारी एक वीडियो में शेफाली ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद खास पल है। उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेट को अपना पूरा बचपन दिया है। जिस समय छोटे बच्चे अपने मम्मी-पापा के साथ खेलते हैं, उस समय मैने अपने आप को पूरी तरह क्रिकेट को समर्पित किया।

बोस्टन मैराथन 2026: खिताब बचाने उतरेगी जॉन कोरिर और शेरोन लोकेडी

एजेंसी

बोस्टन। बोस्टन मैराथन 2026 में मौजूदा चैंपियन जॉन कोरिर और शेरोन लोकेडी अपने-अपने खिताब बचाने के इरादे से सोमवार को दौड़ेंगे। इस बार दोनों वर्गों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने की उम्मीद है। पुरुष वर्ग में केन्या के धावक जॉन कोरिर लगातार चौथा मैराथन खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने पिछले साल शिकागो और वालेंसिया मैराथन में भी जीत दर्ज की थी। बोस्टन मैराथन 2025 में शुरुआती गिरावट के बावजूद उन्होंने 2:04:45 का समय निकालते हुए इतिहास का तीसरा सबसे तेज प्रदर्शन किया था। इस बार कोरिर को केन्या के बेन्सन किप्रूटो, तंजानिया के अल्फोंस फेलिक्स सिम्बू और केन्या के साइब्रियन कोटुट से कड़ी चुनौती मिलेगी। किप्रूटो, जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी मैराथन भी जीती है, 2:02:16 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ इस रेस के सबसे तेज धावक हैं। महिला वर्ग में शेरोन लोकेडी भी खिताब बचाने उतरेंगी। उन्होंने पिछले

साल 2:17:22 का समय निकालकर कोर्स रिकॉर्ड तोड़ा था और हेलेन ओबिरी के दो साल के दबदबे का अंत किया था।

लोकेडी को इस बार केन्या की इरीन चेसाई और इथियोपिया की वर्केनेश एदेसा से चुनौती मिलेगी, जिन्होंने हाल के मैराथन में शानदार प्रदर्शन किया है। जॉन कोरिर ने कहा कि इस बार प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा है और अगर सब कुछ सही रहा तो वह कोर्स रिकॉर्ड को भी चुनौती देने की कोशिश करेंगे। बोस्टन मैराथन 2026 में दुनिया के शीर्ष धावकों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां तेज समय और नए रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना है।

आईपीएल 2026: प्रिंस यादव पर्पल कैप की टॉप-3 में पहुंचे, ऑरेंज कैप रेस भी हुई दिलचस्प

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में खेले गए दो मुकाबलों के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की दौड़ में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने दोनों लीडरबोर्ड को और रोमांचक बना दिया है।

पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2/25 के आंकड़े दर्ज किए। इस मैच में कुल 454 रन बने, लेकिन इसके बावजूद प्रिंस ने किफायती गेंदबाजी की। इस प्रदर्शन के साथ प्रिंस यादव इस सीजन में 11 विकेट तक पहुंच गए हैं और पर्पल कैप की सूची में टॉप-3 में शामिल हो गए हैं। उनके विकेट गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के बराबर हैं, लेकिन बेहतर इकॉनमी रेट के कारण प्रिंस आगे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज 13 विकेट के साथ अब भी शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई 10 विकेट लेकर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

के भुवनेश्वर कुमार भी शीर्ष गेंदबाजों में शामिल हैं। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर और कोलकाता नाइट राइडर्स के कार्तिक त्यागी समेत कई गेंदबाज 8-8 विकेट लेकर प्रतिस्पर्धा को कड़ा बना रहे हैं।

ऑरेंज कैप में टॉप-3 बरकरार, लेकिन रेस हुई और दिलचस्प

ऑरेंज कैप की सूची में टॉप-3 स्थान पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन, गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और आरसीबी के विराट कोहली क्रमशः पहले तीन स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी 46 रनों की पारी के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। पंजाब किंग्स के कूपर कोनॉली ने 46 गेंदों में 87 रन बनाकर छठा स्थान हासिल किया है। उनके साथ राजस्थान के यशस्वी जायसवाल भी 223 रनों के साथ बराबरी पर हैं। वहीं प्रियांश आर्य ने 37 गेंदों में 93 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया है और ऑरेंज कैप की दौड़ को और रोमांचक बना दिया है।

आईपीएल 2026 में जैसे-जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, ऑरेंज और पर्पल कैप की जंग और भी कड़ी होती जा रही है।

पंजाब किंग्स की दमदार जीत, लखनऊ को 54 रन से हराकर शीर्ष पर कायम

एजेंसी

मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़)। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अपनी पांचवीं जीत दर्ज की। खेले गए दूसरे मुकाबले में पंजाब ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान बनाए रखा। इससे पहले दिन के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने मुल्लांपुर स्टेडियम में 7 विकेट खोकर 254 रन बनाए, जो इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। जवाब में लखनऊ की टीम 5 विकेट पर 200 रन ही बना सकी।

पंजाब की पारी की शुरुआत खराब रही और टीम ने 3 रन पर ही प्रभसिमरन सिंह के रूप में पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80

गेंदों में 182 रन की बड़ी साझेदारी की। प्रियांश ने 93 रन और कोनोली ने 87 रन बनाए। अंत में नेहल वाधेरा (13), शशांक सिंह (17) और मार्कस स्टोयनिस (29) की तेज पारियों ने टीम को 250 के पार पहुंचाया। लखनऊ की ओर से एम सिद्धार्थ ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी, मोहसिन खान और प्रिंस यादव को एक-एक सफलता मिली। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत तेज रही और टीम ने 10 ओवर में 100 रन बना लिए थे। हालांकि, इसके बाद लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई।

कप्तान ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जबकि ऐडन मार्करम (42), मिचेल मार्श (40) और आयुष बडोनी (35) ने योगदान दिया, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका। गेंदबाजी में मार्को यानसन ने 2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाख और युजवेंद्र चहल ने एक-एक विकेट झटका। इस जीत के साथ पंजाब 11 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि लखनऊ लगातार तीसरी हार के बाद आठवें स्थान पर है।

कानपुर मंडल की टीम ने टाइब्रेकर में जीती अंतर मंडलीय प्रदेश स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप

एजेंसी

मुरादाबाद। अंडर-20 अंतर मंडलीय प्रदेश स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का आज फ़ाइनल मैच कानपुर और आज़मगढ़ मण्डल की टीम के मध्य एमपीएस ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच में कानपुर मंडल की टीम टाइब्रेकर में विजयी बनी। विजेता टीम को आज सम्मानित किया। वहीं रनर रही आजमगढ़ मंडल की टीम के खिलाड़ियों को भी टॉफी देकर सम्मानित किया गया। ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन मुरादाबाद के महासचिव मुहम्मद नासिर कमाल ने बताया कि खेल का पहले मध्यांतर तक स्कोर 1-0 रहा, खेल मे दूसरे मध्यांतर में आजमगढ़ ने योजनाबद्ध तरीके से कानपुर के गोल पर आक्रमण कर खेल को आपने पक्ष मे करने का पूरा प्रयास किया परन्तु खेल के अंतिम क्षणों में आजमगढ़ के फारवर्ड ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। स्कोर बराबर होने पर निर्णायक ने नियमानुसार टाइब्रेकर का सहारा लिया जिसमें कानपुर के खिलाड़ियों ने अपओ सभी किक गोल किए परन्तु आजमगढ़ के एक खिलाडी की किक कानपुर के गोलकीपर ने रोक

कर अपनी टीम को चैंपियन बनाया। मुख्य अतिथि एमपीएस के एडमिस्ट्रेटर के पुत्र डॉ. आमिर आलम रहे। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद नासिर कमाल ने मुख्य अतिथि को बुके व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि द्वारा विनर व रनर टीम को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

वोल्वार्ड्ट-लूस की तूफानी पारियों से दक्षिण अफ्रीका की भारत पर आसान जीत, सीरीज में 2-0 की बढ़त

एजेंसी

डरबन। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को आठ विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। किंग्समीड मैदान पर खेले गए इस मैच में कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और सुने लुस ने शानदार प्रतिभावान पारियां खिलाड़ी भारतीय टीम की ओर से पूरी तरह से शानदार प्रदर्शन किया। 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने दमदार शुरुआत की। दोनों ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी कर मैच को एकतरफा बना दिया। वोल्वार्ड्ट ने 34 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं लूस ने 46 गेंदों में 57 रन की संयमित पारी खेली। भारतीय टीम को पहली सफलता श्रेयांका पाटिल Patil ने

दिलाई, जिन्होंने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट किया। हालांकि तब तक मैच पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में झुक चुका था। इसके बाद तजमिन ब्रिट्स (नाबाद 20) और एनेरी डेर्कसेन (नाबाद 12) ने टीम को 17 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। इससे पहले भारत की बल्लेबाजी भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हालांकि शैफाली वर्मा ने 57 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन मिडिल ऑर्डर के लगातार विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी और 148 रन तक ही सीमित रह गई।

भारतीय टीम की हार में खराब फील्डिंग भी एक बड़ा कारण रही। अहम मौकों पर कैच छूटे, जिससे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को अतिरिक्त मौके मिले। गेंदबाज भी दबाव बनाने में नाकाम रहे और रन रोकने में असफल दिखे। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में मजबूत पकड़ बना ली है, जबकि भारत के लिए वापसी करना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगले मुकाबले में भारतीय टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, वरना सीरीज हाथ से निकल सकती है।

वाराणसी में ग्रीष्मकालीन टी 20 क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रशासन की टीम ने जीता मैच

एजेंसी

वाराणसी। वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के मार्गदर्शन और मंडल क्रीड़ा अधिकारी बलेन्द्र पाल के नेतृत्व में वाराणसी मंडल क्रीड़ा स्थल में अंतर विभागीय ग्रीष्मकालीन टी 20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रशासन और आर.वी.एन.एल के बीच खेले गए मैच में प्रशासन की टीम विजेता रही।

पहले आर.वी.एन.एल की टीम ने बैटिंग किया और निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 193 रन बनाए। आर.वी.एन.एल की तरफ से चंचल यादव ने 58 बाल पर 11 चौके और 5 छक्के की मदद से 101 रन, ज्ञान वर्मा ने 25 और कार्तिकेय पाठक ने 18 रन बनाए। प्रशासन की तरफ से कलाम अली खान ने चार ओवर में 24 रन लेकर तीन विकेट लिए राकेश, असलम और आशीष को एक-एक

विकेट प्राप्त हुआ। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रशासन की टीम ने 12.5 ओवर में दो विकेट पर 195 रन बनाकर आठ विकेट से मैच जीत लिया।

वही, प्रशासन की तरफ से आशीष यादव ने 30 बाल पर 7 चौके और पांच छक्के की मदद से 66 रन, ऋषि कपूर ने 27 बाल पर छह चौके और छह छक्के की मदद से 65 रन, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिनव सिंह ने सात बाल पर दो चौके और दो छक्के की मदद से 21 रन और असलम ने 16 रन बनाए। आर.वी.एन.एल की तरफ से चंचल यादव और अमितोष राय को एक-एक विकेट प्राप्त हुआ। मैच के अंत में प्रशासन के कलाम अली खान को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आर.वी.एन.एल के ए.जी.एम सत्य प्रकाश यादव द्वारा दिया गया।

जडेजा को इस्तेमाल न करने पर भड़के अश्विन, रियान पराग की कप्तानी पर उठे सवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। Rajasthan Royals को Kolkata Knight Riders के खिलाफ आखिरी ओवर के रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता में खेले गए इस मैच में Rinku Singh ने 34 गेंदों में नाबाद 53 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई।

अश्विन ने पराग की रणनीति पर उठाए सवाल

मैच के बाद अनुभवी स्पिनर Ravichandran Ashwin ने कप्तान Riyan Parag के फैसलों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खासतौर पर Ravindra Jadeja का पूरा इस्तेमाल न करने को बड़ी गलती बताया। अश्विन ने कहा, 'आपके पास वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिसने 3 ओवर में सिर्फ 9-11 रन देकर 2 विकेट लिए। ऐसे में उसे चौथा ओवर न देना समझ से परे है।'

'माइंडसेट' पर उठाया सवाल

अश्विन ने आगे कहा कि यह सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि कप्तान के 'माइंडसेट' की समस्या है। 'आपको लगा कि ऑफ स्पिनर दबाव बना सकता है, लेकिन जडेजा नहीं। यह सोच सही नहीं है। अगर आप अपने बॉलर पर भरोसा नहीं दिखाएंगे, तो लंबे समय में टीम को नुकसान होगा।' उन्होंने साफ किया कि भले ही जडेजा रन दे देते, लेकिन उन्हें मौका देना जरूरी था।

कोलकाता ने इस सीजन दर्ज की पहली जीत, राजस्थान को 4 विकेट से हराया

एजेंसी

कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेले गए मैच में केकेआर ने राजस्थान रॉयल (आरआर) को 4 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम ने रिंकू सिंह की 34 गेंदों में नाबाद 53 रन की अर्धशतकीय और अनुकूल रॉय की 16 गेंदों में 29 रन की नाबाद पारियों के दम पर 19.4 ओवर में छह विकेट पर 161 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

कोलकाता इस सीजन अब तक सात मैच खेल चुकी है। टीम को पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। टीम तीन अंकों के साथ अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। वहीं राजस्थान की 6 मैचों में यह दूसरी हार है। टीम ने चार मैचों में जीत दर्ज की है और उसके आठ अंक है। राजस्थान अंक

तालिका में तीसरे नंबर पर है।

156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पांच रन के अंदर दो विकेट गंवा दिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे और टिम सेफर्ट खाता खोले बिना आउट हुए। पिछले मैच में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले कैमरन ग्रीन भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी 10 रन, रोवमैन पॉवेल 23 रन बनाकर और रमनदीप सिंह 10 रन बनाकर आउट हुए। टीम ने 85 रन तक छह विकेट खो दिए। छह झटके लगने के बाद रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों खिलाड़ियों ने सातवें विकेट के लिए 76 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को इस सीजन की पहली जीत दिला दी। रिंकू ने 34 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 53 रन और अनुकूल ने 16 गेंदों में एक चौका और दो छक्के की मदद से 29 रन की नाबाद पीरियां खेली। राजस्थान की ओर से रवींद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और यशराज पुंजा ने एक-एक विकेच हासिल किया।

मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 155 रन बनाए थे। राजस्थान को सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई। वैभव ने 28 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 46 रन बनाए, जबकि यशस्वी ने 29 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 39 रन की पारी खेली। इन दोनों का विकेट गिरने के बाद राजस्थान की पारी लड़खड़ा गई। टीम का अन्य कोई बल्लेबाजी बल्ले से कमाल नहीं दिखा सका। शिमरॉन हेत्मायर ने 15 रन और कप्तान रियान पराग ने 12 रन, रवीन्द्र जडेजा 09 रन, जोफ्रा आर्चर 08 रन और डोनोवन फरेरा ने 07 रन का योगदान दिया। कोलकाता के लिए कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती ने तीन-तीन विकेट झटके, जबकि सुनील नरेन को दो विकेट मिले।

बिंदी-तिलक विवाद के बाद लेंसकार्ट का बड़ा यू-टर्न, सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बीच कंपनी ने मांगी माफी

एजेंसी
नई दिल्ली। आईवियर रिटेलर दिग्गज लेंसकार्ट (Lenskart) ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी विवादास्पद ड्रेसकोड को लेकर मचे हंगामे के बाद औपचारिक रूप से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर कंपनी के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों और 'बॉयकॉट लेंसकार्ट' जैसे ट्रेंड्स के बाद, कंपनी ने एक नया आधिकारिक बयान जारी किया है। लेंसकार्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी टीम के सदस्यों द्वारा धारण किए जाने वाले आस्था और संस्कृति के सभी प्रतीक जैसे बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी का अब बिना किसी शर्त के स्वागत है। कंपनी ने इन प्रतीकों को अपनी पहचान का अभिन्न अंग बताया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब लेंसकार्ट के कुछ स्टोर्स के लिए एक स्टाइल गाइडलाइन सार्वजनिक हुई, जिसमें हिंदू कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से मना किया गया था। साथ ही, शादीशुदा महिलाओं को भी सिंदूर बेहद कम मात्रा में लगाने का निर्देश दिया गया था। दूसरी ओर, हिजाब और पगड़ी पहनने की अनुमति दी गई थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भेदभाव के आरोप लगे। कंपनी ने अब स्वीकार किया है कि यदि उनकी किसी नीति या संवाद से किसी कर्मचारी या ग्राहक की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उन्हें इसका गहरा दुख है।

भारतीय रेलवे की आय में ऐतिहासिक उछालः कबाड़ बेचकर कमाए 6,800 करोड़ रुपये से अधिक

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन पर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, रेलवे ने पुराने कबाड़ की बिक्री (स्क्रैप) की बिक्री से कुल 6,813.86 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित 6,000 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य से लगभग 13.5 प्रतिशत अधिक है। रेलवे द्वारा अनुपयोगी पटरियों, पुराने कोचों और इंजनों की पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया के कारण यह सफलता मिली है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब रेलवे ने अपने कबाड़ बिक्री के लक्ष्य को बड़े अंतर से पार किया है। स्क्रैप की बिक्री के साथ-साथ रेलवे ने 'गैर-किराया आय' में भी शानदार प्रदर्शन किया है। विज्ञापन, स्टेशन पुनर्विकास और व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाली आय में पिछले पांच वर्षों में करीब 168 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यह आय वर्ष 2021-22 के 290 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 777.76 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच गई है। इस रणनीति से रेलवे को यात्रियों पर टिकट का बोझ डाले बिना अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिली है। इसके लिए प्रीमियम ब्रांडेड आउटलेट्स और डिजिटल सेवाओं को प्रमुख जरिया बनाया गया है। कबाड़ के इस व्यवस्थित निपटान से रेलवे परिसरों, यार्डों और वर्कशॉप में सालों से दबी हुई बहुमूल्य जगह खाली हुई है, जिससे परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार हुआ है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 'वेस्ट-टू-वेल्थ' अभियान के तहत अर्जित इस अतिरिक्त आय का निवेश रेल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में किया जाएगा।

एफपीआई ने अप्रैल में पूंजी बाजार से निकाले 58,403 करोड़ रुपये

मुंबई। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने अप्रैल में अब तक भारतीय पूंजी बाजार से कुल 58,403 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है।शुद्ध निकासी, बाजार में लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर होता है। यह लगातार दूसरा महीना है जब एफपीआई बाजार में बिकवाल दिख रहे हैं। इससे पहले मार्च में उन्होंने रिकॉर्ड 1,26,991 करोड़ रुपये की निकासी की थी। केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा (सीडीएसएल) के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने अप्रैल में अब तक इक्विटी में 43,419 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। डेट और हाइब्रिड उपकरणों में भी उनका निवेश नकारात्मक रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में उन्होंने शुद्ध रूप से पैसा लगाया है।डेट में उन्होंने 15,320 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। हाइब्रिड उपकरणों से भी उन्होंने 13.5 करोड़ रुपये निकाले हैं।म्यूचुअल फंड में अप्रैल में एफपीआई का शुद्ध निवेश 350 करोड़ रुपये रहा है। एफपीआई ने मौजूद कैलेंडर वर्ष में भारतीय पूंजी बाजार में 1,76,617 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। इसमें अकेले इक्विटी से ही उन्होंने 1,74,540 करोड़ रुपये निकाले हैं।

सीआईआई ने दिया राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक बनाने का सुझाव

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने देश में उद्योगों के विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक बनाने का सुझाव दिया है।परिसंघ की जारी रिपोर्ट में कहा इस बात पर जोर दिया गया है कि निवेश को तेज करने, परियोजनाओं में लगने वाले समय को कम करने और देश को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक भूमि तक कुशल और पारदर्शी पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।सीआईआई का कहना है कि विनिर्माण, अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के लिए औद्योगिक भूमि एक बुनियादी संसाधन है। विभिन्न राज्यों में वर्तमान व्यवस्था खंडित प्रक्रियाओं, जटिल विनियमों, अस्पष्ट भूमि शीर्षक, कब्ज़ा मिलने में देरी और आवंटित भूमि के कम उपयोग जैसी समस्याओं से ग्रस्त है।

भुवनेश्वर में देश की पहली त्रि-आयामी चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी गई

एजेंसी
भुवनेश्वर। केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओडिशा में भुवनेश्वर के इंफो वैली में भारत की पहली उन्नत त्रि-आयामी (3 डी) चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी। इसे उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना की आधारशिला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रखी। यह इकाई देश के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी और रक्षा क्षेत्र को भी नई गति देगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और

ओडिशा इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। यह परियोजना देश की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में छह गुना वृद्धि हुई है और भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है, जबकि 2025 में मोबाइल फोन निर्यात में भी अग्रणी बना है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसे राज्य और देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि पहली बार भारत में इस स्तर की उन्नत सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित की जा रही है। इससे ओडिशा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और इसमें प्रतिवर्ष 70 हजार ग्लास पैनल, 5 करोड़ असेंबल्ड यूनिट तथा करीब 13 हजार उन्नत मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि ओडिशा तेजी से सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है और राज्य सरकार की नीतियां निवेश आकर्षित करने तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक साबित हो रही हैं। यह परियोजना अमेरिका की कंपनी 3डी ग्लास सॉल्यूशंस की भारतीय इकाई द्वारा खोरधा जिले में स्थापित की जा रही है। कुल निवेश लगभग 1943 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता शामिल है। यह इकाई डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, 5जी/6जी संचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी। इसका वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त 2028 से शुरू होने और 2030 तक पूर्ण क्षमता प्राप्त करने की संभावना है।

200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस : जैकलीन फर्नांडिस की अप्रूवर बनने की अर्जी पर सुनवाई टली, अब 8 मई को होगा फैसला

एजेंसी
नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। दरअसल, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की ओर से सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने के लिए दाखिल अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है, साथ ही एजेंसी ने जैकलीन की इस अर्जी का विरोध भी किया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने कहा कि जैकलीन की ओर से दायर की गई अर्जी आधारहीन है। साथ ही एजेंसी ने अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जैकलीन की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। इस हाई-प्रोफाइल केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम तब सामने आया था, जब जांच एजेंसी ने दावा किया कि सुकेश ने ठगी के पैसों से उन्हें कई महंगे गिफ्ट्स दिए थे। इसी आधार पर ईडी ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया था। जैकलीन ने हाल ही में कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह इच्छा जताई थी कि वह इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईडी ने उनके इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल उनकी अर्जी को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फिर से बंद होने से कच्चे तेल में उछाल, ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के पार

एजेंसी
नई दिल्ली। ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा बंद करने के फैसले से सोमवार को कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर से 95 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है। सुबह 10:40 पर ब्रेंट क्रूड 5.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 95.40 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 6.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ 87.63 डॉलर प्रति बैरल पर था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल का 18 मई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 6.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 8,175 रुपए पर था।

कच्चे तेल में उछाल की वजह ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद करना है। साथ ही, ईरान ने नाविकों को चेतावनी दी है कि अगर कोई स्ट्रेट को बिना मंजूरी के पार करता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

दूसरी तरफ, अमेरिका ने भी सख्त रूख अपनाया हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि

तेहरान जलमार्ग को बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता।

वहीं, ईरान ने कहा कि वह अपने बंदरगाहों की निरंतर अमेरिकी नाकाबंदी का जवाब दे रहा है। साथ ही, इसे युद्धविराम का उल्लंघन बताया। वहीं, सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा कि देश की नौसेना अपने दुश्मनों को 'नई करारी हार' देने के लिए तैयार है।

अमेरिका की कार्रवाई जारी है। उसने ईरान के एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है जिसने उसकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। इसके जवाब में तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और इस बात पर संदेह पैदा हो गया है कि दोनों देशों के बीच निर्धारित दो दिनों का युद्धविराम भी कायम रह पाएगा या नहीं। इस बीच, वैश्विक अस्थिरता के बीच घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले।

एशियाई बाजारों में सकारात्मक प्रदर्शन देखने को मिला, जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1 प्रतिशत तक बढ़ा। पिछले सत्र में अमेरिकी बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए, एस एंड पी 500 1.2 प्रतिशत और नैस्डैक 1.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने से सोने और चांदी करीब 2 प्रतिशत तक फिसले

एजेंसी
मुंबई। अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ने से सोमवार को सोने और चांदी दबाव के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं में करीब 2 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 9:50 पर सोने का 5 जून 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 1.06 प्रतिशत या 1,641 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,968 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,52,829 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,53,251 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि एमसीएक्स गोल्ड की शुरुआत मामूली गैप डाउन के साथ हुई, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी की बढ़ती दिलचस्पी के चलते यह 1,52,000 रुपए के स्तर से ऊपर बना हुआ है। अगर यह 1,55,000 रुपए से ऊपर निकलता है तो यह 1,57,000-1,58,000 रुपए के स्तर तक जा सकता है। दूसरी ओर, 1,52,500 रुपए से नीचे टूटने पर, यह 1,51,000-1,50,000 रुपए और उससे आगे 1,48,000 रुपए तक जा सकता है।चांदी का 5 मई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 1.96 प्रतिशत या

5,045 रुपए की गिरावट के साथ 2,52,100 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,52,016 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,54,089 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है। चांदी पर विश्लेषक ने कहा कि चांदी गैप डाउन के साथ 2,52,000 रुपए के आसपास बनी हुई है। इसके लिए रुकावट का स्तर 2,55,000-2,60,000 रुपए है और अगर यह इस स्तर को तोड़ता है तो 2,68,000-2,70,000 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगर चांदी 2,48,000 रुपए का स्तर तोड़ती है तो यह 2,44,000-2,40,000 रुपए के स्तर तक जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में दबाव देखा जा रहा है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 1.34 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,814 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80 डॉलर प्रति औंस पर थी।

हिमाचल में वेतन कटौती लागू : मुख्य सचिव और डीजीपी समेत अधिकारियों पर भी असर

एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत विधायकों के वेतन में कटौती के कुछ दिनों बाद मुख्य सचिव संजय गुप्ता और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी समेत वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के वेतन में भी अस्थायी रूप से 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। कांग्रेस सरकार ने इस पहाड़ी राज्य में चल रहे आर्थिक संकट से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर अगले छह महीनों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी के एक हिस्से को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। वित्त विभाग के सचिव आशीष सिंहमार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मुख्य सचिव की सैलरी से हर महीने 1.10 लाख रुपए, अतिरिक्त मुख्य सचिव की सैलरी से 1.05 लाख रुपए, प्रधान सचिव की सैलरी से 97,500 रुपए और सचिव की सैलरी से 60,000 रुपए की राशि छह महीनों के लिए रोक दी जाएगी। यह व्यवस्था अप्रैल की सैलरी से

लागू होगी, जो मई में मिलेगी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह कदम राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति से निपटने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

राज्य सरकार ने बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालयों और अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को भी इस फैसले को लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम अस्थायी है और राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के सामूहिक प्रयास का एक हिस्सा है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, हिमाचल प्रशासनिक सेवा रैंक से प्रमोट होकर विभाग प्रमुख बने अधिकारियों को हर महीने 3.10 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, जबकि आईएएस अधिकारियों को लगभग 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। प्रदेश सरकार के पास लगभग 60 विभाग प्रमुख हैं, और इस अस्थायी सैलरी कटौती से लगभग 200 अधिकारी प्रभावित होंगे। उनकी सैलरी में हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की कटौती होने की संभावना है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और प्रधान सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी उन अधिकारियों में शामिल किया गया है जिनकी सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। -आईएएनएसस्कोडा कोडियाक अपनी श्रेणी के अन्य लोकप्रिय मॉडलों को कड़ी टक्कर देती है।

अपनी मजबूती, उन्नत तकनीक और प्रीमियम सुविधाओं के कारण यह वाहन ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यदि आप एक ऐसी एसयूवी की तलाश में हैं जो शक्ति, सुविधा और आधुनिक तकनीक का संतुलित मेल प्रदान करे, तो यह ऑफर आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है।

भारतीय टैंकर 'देश गरिमा' ने सुरक्षित पार किया होर्मुज, 22 अप्रैल को पहुंचेगा मुंबई

एजेंसी
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत के ध्वज वाले तेल के टैंकर 'देश गरिमा' ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इस जहाज के 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की संभावना जताई गई है। इस जहाज पर 31 भारतीय नाविक सवार है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर देश गरिमा ने 18 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इस जहाज में 31 भारतीय नाविक सवार है, इसके 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय टैंकर ने इस तनाव-ग्रस्त जलमार्ग को ऐसे समय पार किया है, जब दो अन्य भारतीय जहाजों को गोलीबारी के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद भारत ने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता को ईरान के साथ साझा किया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में, दो भारतीय पोतों, वीएलसीसी समनार हेराड और बल्क कैरियर जग अर्नव, ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय

गोलीबारी की घटना की सूचना दी, जिसके बाद वे फारस की खाड़ी में लौट आए। फिलहाल चालक दल के किसी भी सदस्य के घायल होने की कोई खबर नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर ईरान के राजदूत को तलब करके गहरी चिंता व्यक्त की थी।

घरेलू सर्राफा बाजार में चमकी चांदी, एक महीने में 27 हजार रुपये तक बढ़ी कीमत

एजेंसी
नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में हाजिर चांदी ने एक बार फिर जबरदस्त छलांग लगाई है। कारोबार में इस चमकीली धातु की कीमत में 10 हजार रुपये प्रति किलोग्राम से भी अधिक की तेजी आई है। चांदी के भाव में आए उछाल के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में चांदी आज 2,74,800 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 2,80,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक के भाव पर बिक रही है। दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी आज 10,100 रुपये प्रति किलोग्राम उछल गई, जिसके कारण ये चमकीली धातु आज 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसी तरह मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में चांदी 2,74,800 रुपये के भाव पर कारोबार कर रही है। जयपुर, सूरत और पुणे में चांदी 2,75,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। बेंगलुरु में चांदी 2,75,300 रुपये के स्तर पर और पटना तथा भुवनेश्वर में 2,74,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसके अलावा हैदराबाद में चांदी 10,200 रुपये प्रति

किलोग्राम की तेजी के साथ 2,79,800 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। देश में चांदी की सबसे अधिक कीमत आज भी चेन्नई में है, जहां ये चमकीली धातु आज 10,500 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी होकर 2,80,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। मार्केट एक्सपर्ट मयंक मोहन का कहना है कि पश्चिम एशिया में जंग थमने की उम्मीद से सोना और चांदी की कीमत को सपोर्ट मिला है। खासकर, डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी ने निवेशकों का रुझान इन दोनों चमकीली धातुओं की ओर बढ़ा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच घरेलू सर्राफा बाजार पिछले एक महीने की अवधि में चांदी की कीमत में करीब 27 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक की तेजी दर्ज की गई है। मयंक मोहन के अनुसार फिलहाल पश्चिम एशिया में जारी जंग की वजह से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड में गिरावट आ गई है। इसलिए फिलहाल इस चमकीली धातु की कीमत मे जोरदार उछाल का रुख नहीं बन पा रहा है। पश्चिम एशिया में शांति का माहौल बनने के बाद औद्योगिक गतिविधियां तेज होने पर चांदी की मांग भी बढ़ जाएगी। ऐसा होने पर इस चमकीली धातु की कीमत में दोबार तेजी आने की उम्मीद बनी हुई है।

सोनीपत की 21 मंडियों में गेहूं खरीद हुई दो लाख 80 हजार मीट्रिक टन

एजेंसी
सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले की अलग-अलग अनाज मंडियों और खरीद केन्द्रों में गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है। 21 मंडियों और खरीद केन्द्रों में दो लाख 80 हजार 904.3 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा और सभी सरकारी एजेंसियों ने तय समर्थन मूल्य पर खरीद पूरी की। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि देर सायं तक कुल खरीदे गए गेहूं में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 44 हजार 90 मीट्रिक टन, हैफेड ने एक लाख नौ हजार 835 मीट्रिक टन, हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने एक लाख 25 हजार 431.12 मीट्रिक टन और एफसीआई ने एक हजार 548 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। सभी एजेंसियां मिलकर खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से चला रही हैं। खरीद केन्द्रों के अनुसार गांव बरोदा में दो हजार 60 मीट्रिक टन, भैंसवाल में तीन हजार 555 मीट्रिक टन, बिचपड़ी में 375 मीट्रिक टन और दातौली में पांच हजार 220.7 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।

फरमाणा केन्द्र पर आठ हजार 797.2 मीट्रिक टन, गन्नौर अनाज मंडी में 17 हजार 646.5 मीट्रिक टन और गोहाना अनाज मंडी में सबसे अधिक एक लाख 13 हजार 435.6 मीट्रिक टन खरीद दर्ज की गई। कांसड़ी में छह हजार 625 मीट्रिक टन और कथूरा में चार हजार 465.4 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इसी तरह खानपुर में पांच हजार 304.22 मीट्रिक टन, खरखौदा अनाज मंडी में 32 हजार 448.5 मीट्रिक टन, मुडलाना में पांच हजार 105 मीट्रिक टन और मुरथल में चार हजार 760.5 मीट्रिक टन खरीद हुई। नाहरा में चार हजार 60 मीट्रिक टन, पुगथला में 10 हजार 51.2 मीट्रिक टन, पुरखास में पांच हजार 700.1 मीट्रिक टन, रूखी में छह हजार 754.7 मीट्रिक टन और सनपेड़ा में छह हजार 195.5 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सोनीपत अनाज मंडी में 36 हजार 796.2 मीट्रिक टन और सोनीपत सीलो केन्द्र पर एक हजार 548 मीट्रिक टन खरीद पूरी हुई।

अब तक 16 हजार 734 किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचे हैं। सभी किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। प्रशासन का कहना है कि भुगतान और उठान प्रक्रिया भी तेज गति से जारी है, ताकि किसानों को समय पर पूरा लाभ मिल सके।

पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर सरकार कर रही विचार

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100 फीसदी तक करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि यह कदम बीमा क्षेत्र के अनुरूप होगा, जहां सरकार की ओर से पहले ही 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा चुकी है। पिछले वर्ष संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी।

सूत्रों के मुताबिक पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की अधिनियम, 2013 में संशोधन कर पेंशन क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव मानसून या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। फिलहाल पेंशन कोष में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी है। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान भी शामिल हो सकता है। वर्तमान में एनपीएस ट्रस्ट की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां वर्ष 2015 के नियमों के तहत निर्धारित हैं, जिन्हें भविष्य में किसी धर्मार्थ ट्रस्ट या कंपनी कानून के तहत लाया जा सकता है।

अगले सप्ताह सिर्फ एक नए आईपीओ की लॉन्चिंग, दो कंपिनियों के शेयरों की होगी लिस्टिंग

एजेंसी
नई दिल्ली। शुरू होने वाले कारोबारी सप्ताह के दौरान प्राइमरी मार्केट काफी हद तक शांत रहने वाला है। इस सप्ताह सिर्फ एक कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। इस नए आईपीओ के अलावा पिछले सप्ताह खुले दो आईपीओ में भी इस सप्ताह निवेशक अपनी बोली लगा सकेंगे। जहां तक नई लिस्टिंग की बात है, तो इस सप्ताह जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। इस सप्ताह खुलने वाला एकमात्र आईपीओ लीपफोर्ज इंजीनियरिंग का है। कंपनी का 79.60 करोड़ रुपये का आईपीओ गुरुवार यानी 23 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस इश्यू में 27 अप्रैल तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 21 रुपये से लेकर 23 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 6,000 शेयर का है। आईपीओ की क्लोजिंग के बाद 28 अप्रैल को अलॉटमेंट फाइनल किया जाएगा, जबकि 30 अप्रैल को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग हो सकती है। इन नए आईपीओ के अलावा पिछले सप्ताह 17 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए खुले सिटियस ट्रांसनेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट के 1,105 करोड़ रुपये के आईपीओ में मंगलवार यानी 21 अप्रैल तक बोली लगाई जा सकती है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 99 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 24 अप्रैल को शेयरों का अलॉटमेंट हो सकता है, जबकि 29 अप्रैल को कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं।

अभी तक इस पब्लिक इश्यू को 69 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। इसी तरह 17 अप्रैल को ही सब्सक्रिप्शन के लिए खुले मेहुल टेलिकॉम के 27.73 करोड़ रुपये के आईपीओ में भी मंगलवार यानी 21 अप्रैल तक बोली लगाई जा सकती है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 96 रुपये से लेकर 98 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,200 शेयर का है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 22 अप्रैल को शेयरों का अलॉटमेंट हो सकता है, जबकि 24 अप्रैल को कंपनी के शेयर बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। अभी तक ये पब्लिक इश्यू 3.64 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।

जहां तक शेयर बाजार में लिस्टिंग की बात है, तो इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन प्रॉपशेयर सेलेस्टिया के शेयरों की बीएसई पर लिस्टिंग हो सकती है। यह प्रॉपर्टी शेयर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट आरआआईटी की तीसरी स्कीम है। इसी दिन मेहुल टेलिकॉम के शेयर भी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होकर स्टॉक मार्केट में अपने कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं।

ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर में हिस्सा लेने से इनकार किया

एजेंसी

तेहरान। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि देश ने अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा था कि यह वार्ता जल्द ही पाकिस्तान में होने वाली थी। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने अंग्रेजी अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि वार्ता के दूसरे दौर से ईरान की अनुपस्थिति का कारण अमेरिका की 'बहुत ज्यादा मांगें, अव्यवहारिक उम्मीदें, बार-बार अपने रुख में बदलाव, विरोधाभासी बयान और समुद्री नाकाबंदी' हैं। ईरान का मानना है कि यह नाकाबंदी युद्धविराम का उल्लंघन है। आईआरएनए ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, वे सही नहीं हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने फारसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। एजेंसी ने अमेरिका की ओर से आई खबरों को 'मीडिया का खेल' और 'दोषारोपण की रणनीति' बताया, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बनाना है। उसने कहा कि अमेरिका की 'अत्यधिक, तर्कहीन और अव्यवहारिक मांगों, बार-बार बदलता रुख, विरोधाभासी बयान और कथित समुद्री नाकाबंदी' की वजह से अब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। आईआरएनए ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में बातचीत से किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद बहुत कम है। 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान और ईरान के कई अन्य शहरों पर हमले किए थे। इन हमलों में उस समय के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और आम नागरिक मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और होर्मुज जलडमरूमध्य पर कड़ा नियंत्रण कर लिया।

8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम हुआ। इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच लंबी बातचीत हुई। लेकिन यह वार्ता सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद अमेरिका ने जलमार्ग पर अपनी नाकाबंदी लागू कर दी। खबरों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच जल्द ही पाकिस्तान में एक और दौर की शांति वार्ता होने की उम्मीद थी।

ईयू उपाध्यक्ष के बयान पर ईरान का पलटवार, अंतरराष्ट्रीय कानून की बातों को इस्माइल बाघेई ने बताया चरम पाखंड

एजेंसी

तेहरान। ईरान ने अमेरिका पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज स्ट्रेट बिना किसी शुल्क के खुला रहना चाहिए। इस पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने ईसी उपाध्यक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। ईरानी नेता इस्माइल बाघेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काजा कल्लास के पोस्ट को रिशेयर कर लिखा, 'ओह, वो 'अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसे ईयू दूसरों को भाषण देने के लिए इस्तेमाल करता है, चुपचाप अमेरिका-इजरायल के बीच आक्रामक युद्ध को हरी झंडी दे देता है और ईरानियों पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा कर देता है।' बाघेई ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई पर यूरोपीय संघ के बयान केवल उपदेश तक सीमित हैं, जबकि व्यवहार में यूरोप अपने ही सिद्धांतों पर अमल करने में बार-बार विफल रहा है। उन्होंने कहा, 'उपदेशों को रहने दें। यूरोप जो कहता है, उसे करने में लगातार नाकाम रहा है, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय कानून की बातें चरम पाखंड बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई भी नियम ईरान को एक तटीय देश होने के नाते होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने से नहीं रोकता है।'

रूस से ऊर्जा आपूर्ति बंद होने से यूरोप छोड़ रहे हैं उद्योगः गास्पर

एजेंसी

ब्रातिस्लावा। स्लोवाक संसद के उपाध्यक्ष टिबोर गास्पर ने कहा है कि पूर्व से मिलने वाली स्थिर ऊर्जा आपूर्ति पर आधारित यूरोपीय उद्योग अब उसके अभाव में यूरोपीय संघ से बाहर स्थानांतरित हो रहे हैं। श्री गास्पर ने कहा कि रूस के ऊर्जा संसाधन लंबे समय तक अन्य विकल्पों की तुलना में सस्ते रहे हैं और उनकी वापसी से उद्योग, महंगाई और आम उपभोक्ताओं पर दबाव कम होगा।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जर्मनी और मध्य यूरोप का औद्योगिक ढांचा पूर्व से मिलने वाली ऊर्जा पर टिका रहा है। उन्होंने कहा कि सस्ती ऊर्जा के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी नहीं रह सकती और इसी कारण उत्पादन अब यूरोपीय संघ से बाहर जा रहा है। श्री गास्पर के अनुसार, ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण किसी एक आपूर्तिकर्ता को स्थायी रूप से बाहर करना नहीं है, बल्कि विकल्पों को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि रूस एक विकल्प हो सकता है, न कि एकमात्र, लेकिन उसे पूरी तरह प्रतिबंधित करना भी उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल एलएनजी, विशेषकर अमेरिका से, पर निर्भरता के बजाय अधिक आपूर्तिकर्ता होने से बेहतर कीमतें और अधिक स्वतंत्रता मिलती है। श्री गास्पर ने कहा कि रूसी तेल की वापसी 'पीछे जाने का कदम नहीं, बल्कि यथार्थवादी ऊर्जा नीति की दिशा में कदम' होगा और विचारधारा को आर्थिक स्थिरता व नागरिकों के जीवन स्तर पर हावी नहीं होना चाहिए। इस बीच, यूरोपीय संघ परिषद ने पहले ही एक जनवरी 2027 से रूसी एलएनजी आयात और 30 सितंबर 2027 से रूसी पाइपलाइन गैस पर प्रतिबंध को अंतिम मंजूरी दे दी है।

अमेरिकी प्रतिबंध के बाद क्यूबा में ईंधन संकट गहराया, स्पेन समेत कई देशों ने जताई चिंता

मैड्रिड। जनवरी के आखिर में वॉशिंगटन द्वारा तेल की सप्लाई रोकने के बाद क्यूबा की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है ईंधन के अभाव में इन तीन महीनों में वहां मानवीय स्थिति एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। इस बीच ब्राजील, मैक्सिको और स्पेन की सरकारों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और स्थिति को आसान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। स्पेन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को तीनों सरकारों ने संबंधित पक्षों से यह भी अपील की कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचें, जिससे लोगों के जीवन की स्थितियां और खराब हों या जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो। इसके साथ ही उन्होंने क्यूबा के लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए एक समन्वित तरीके से अपनी मानवीय सहायता को बढ़ाने का भी संकल्प लिया। अपने बयान में ब्राजील, स्पेन और मैक्सिको ने हर समय अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की आवश्यकता को भी दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभु समानता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का पालन करने पर भी जोर दिया।

हिजबुल्ला की चेतावनी : इजरायली उल्लंघन का मिलेगा करारा जवाब, लेबनान सरकार के साथ नई शुरुआत की तैयारी

बेरुत। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा कि इजरायल के साथ संघर्ष-विराम का मतलब पूरी तरह से हमले बंद होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजरायल दक्षिणी लेबनान में किसी तरह का उल्लंघन करता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। कासिम ने अपने बयान में कहा कि एकतरफा संघर्षविराम नहीं हो सकता। उन्होंने साफ किया कि अगर आक्रामक कार्रवाई जारी रहती है, तो हिजबुल्लाह के लड़ाके उसी हिसाब से जवाब देंगे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पांच अहम शर्तें भी रखीं। इनमें पूरे लेबनान में स्थायी रूप से लड़ाई बंद करना, इजरायली सेना की पूरी वापसी, बंदियों की रिहाई, विस्थापित लोगों को वापस बसाना और अरब तथा अंतरराष्ट्रीय मदद से पुनर्निर्माण शामिल है। कासिम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह हार नहीं मानने वाला है और वह लेबनान की आजादी और संप्रभुता के लिए आगे भी प्रयास करता रहेगा। कासिम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह लेबनानी सरकार के साथ सहयोग का 'एक नया अध्याय' शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकारी संस्थानों के साथ काम करने पर जोर दिया।

ईरान का ऐलान : युद्ध पूरी तरह खत्म होने तक होर्मुज स्ट्रेट के ट्रैफिक पर रहेगा नियंत्रण

तेहरान। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएससी) ने कहा है कि जब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर अपना नियंत्रण और निगरानी बनाए रखेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक, यह बयान उस समय आया जब ईरान की मुख्य सैन्य कमान 'खातम अल-अनबिया सेंट्रल मुख्यालय' ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहने के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य पर फिर से सख्त नियंत्रण शुरू किया जा रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एसएनएससी ने बताया कि वह इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से उनकी जानकारी मांगेगा, उन्हें आने-जाने की अनुमति देगा, सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के लिए शुल्क लेगा और अपने नियमों तथा युद्धकालीन व्यवस्था के अनुसार जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगा।

ईरान की स्थिति के कारण यूएई को पड़ सकती है अमेरिका से आर्थिक सहायता की जरूरत

एजेंसी

मास्को। 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत में वित्तीय सहायता की संभावना जतायी है। पश्चिम एशिया का संघर्ष यूएई में संकट को यदि और अधिक गहरा देता है, तो उस स्थिति के लिए यह सहायता मांगी गयी है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ बैठकों के दौरान 'मुद्रा विनिमय मार्ग' (करेंसी स्वैप लाइन) स्थापित करने की संभावना पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अब तक इस संघर्ष के सबसे बुरे आर्थिक परिणामों से खुद को बचाये रखा है, लेकिन उन्हें फिर भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच, कतर के वित्त मंत्री अली बिन

अहमद अल कुवारी ने भी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि दोनों नेताओं ने फारस की खाड़ी पर ईरान के हमलों और उसके आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की। विभाग ने एक बयान में कहा, ' शुक्रवार को वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। मंत्री बेसेंट और मंत्री अल कुवारी ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों के खिलाफ ईरान के हमलों और उनके क्षेत्रीय एवं वैश्विक आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की।' श्री बेसेंट ने इस बात पर बल दिया कि अमेरिका भविष्य में ईरान के हमलों और ऊर्जा एवं अन्य बाजारों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू किये थे, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गये थे। वाशिंगटन और तेहरान ने आठ अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। मध्यस्थ अब बातचीत फिर शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं।

ईरान के मशहद एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू करने को मंजूरी

एजेंसी

तेहरान। ईरान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि उसने सोमवार से उत्तर-पूर्वी प्रांत खोरासन रजावी में मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सि?न्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अथॉरिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में बताया कि यह फैसला पहले की उस घोषणा के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि पूर्वी ईरान का हवाई क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि कुछ एयरपोर्ट्स ने शनिवार सुबह सात बजे (स्थानीय समय) से काम करना फिर शुरू कर दिया है।एजेंसी ने बताया कि अभी घरेलू उड़ानों के टिकट बेचने की इजाजत नहीं दी गई है। ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिससे पूरे देश में नागरिक उड्डयन सेवाएं रुक गई थीं। एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि जैसे ही सैन्य और नागरिक अधिकारियों की तकनीकी और ऑपरेशनल तैयारियां पूरी हो जाएंगी, वैसे-वैसे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट सेवाएं सामान्य होती जाएंगी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में कुछ 'प्रगति' हुई है, लेकिन उसने यह भी कहा कि अंतिम समझौता अभी काफी दूर है। फिलहाल दो हफ्ते का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने कहा कि तेहरान एक तरफ कूटनीतिक कोशिशें कर रहा है, लेकिन साथ ही किसी भी सैन्य टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने विरोधियों पर भरोसा नहीं करता और किसी भी बढ़ते तनाव का जवाब देने के लिए तैयार है। टीवी पर दिए गए संबोधन में उन्होंने कहा कि हालिया संघर्ष बातचीत के दौरान ही शुरू हुआ, और उन्होंने अमेरिका पर 'धोखे' का आरोप लगाया। कलीबाफ ने कहा कि ईरान ने 'मैदान में भी और कूटनीति में भी' सफलता हासिल की है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि तनाव कभी भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और साथ ही हर जरूरी कदम के लिए पूरी तैयारी भी है। उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान अपने विरोधियों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वह स्थायी शांति चाहता है और ऐसे भरोसेमंद आश्वासन चाहता है जिससे बार-बार युद्ध, सीजफायर और फिर संघर्ष का सिलसिला खत्म हो सके।

अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान के जहाज को किया जब्त, ईरानी सेना ने मुंहतोड़ जबाव देने की दी चेतावनी

एजेंसी

वॉशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की और उसे जब्त कर लिया। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिका को इस कार्रवाई का जवाब देने की चेतावनी दी है। ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'ईरान के झंडे वाला टीओयूएसकेए नाम का एक कार्गो शिप, जो लगभग 900 फीट लंबा और लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितने वजन का था, ने हमारे नेवल ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश की। यह उनके लिए ठीक नहीं रहा। अमेरिकी नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस एसपीआरयूएएनसीई ने टीओयूएसकेए को ओमान की खाड़ी में उन्हें रुकने की साफ चेतावनी दी।' ट्रंप ने आगे बताया, 'ईरानी क्रू ने

बात सुनने से मना कर दिया, इसलिए हमारे नेवी शिप ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अभी, अमेरिकी मरीन के पास शिप की कस्टडी है। टीओयूएसकेए पर अमेरिकी वित्त प्रतिबंध लगे हैं क्योंकि पहले भी उसने गैरकानूनी काम किए हैं। शिप की पूरी कस्टडी हमारे पास है और हम देख रहे हैं कि शिप पर क्या है! ' वहीं इसे लेकर ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि वह ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई का जवाब देगी। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी के टेलीग्राम पर एक पोस्ट के मुताबिक, ईरान की सेना ने कहा, 'हमलावर अमेरिका ने सीजफायर तोड़कर और समुद्री रास्ते में डकैती करके, ओमान सागर के पानी में एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला किया। ' ईरानी सेना ने आगे कहा कि अमेरिका ने जहाज के नेविगेशनल इक्विपमेंट को नष्ट कर दिया और डेक पर सैनिकों को तैनात कर दिया है। पोस्ट के आखिर में कहा गया, 'हम चेतावनी देते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना जल्द ही इस अमेरिका की हथियारबंद समुद्री लूट का जवाब देगी और जवाबी कार्रवाई करेगी। 'बता दें, इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी थी कि अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान जा रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरान के जहाज को कब्जे में लेने की जानकारी दी। तेहरान ने सार्वजनिक तौर पर यह पुष्टि नहीं किया है कि वह बैठक के लिए अपने अधिकारियों को भेजेगा, हालांकि ईरानी सोर्स ने अमेरिकी मीडिया सीएनएन को बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचेगा।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन के अनुसार, व्हाइट हाउस के मुताबिक, पाकिस्तान जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल होंगे।

अजरबैजान के रास्ते ईरान से 300 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी, आखिरी बैच से मिले राजदूत अभय कुमार

एजेंसी

अजरबैजान। अजरबैजान के रास्ते ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। अब तक 300 से ज्यादा नागरिकों को निकाला जा चुका है, जिनमें 189 छात्र शामिल हैं। इसी बीच ईरान ने मशहद एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। अजरबैजान के बाकू स्थित भारतीय दूतावास ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया, ''अजरबैजान में भारत के राजदूत अभय कुमार अजरबैजान के रास्ते ईरान से निकाले गए भारतीय छात्रों के आखिरी बैच से मिले। छह मार्च से अब तक अजरबैजान के रास्ते ईरान से 189 छात्रों सहित 300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकाला गया है।'' दो दिन पहले ही नई दिल्ली में हुई साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया था कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 2,361 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित भारत लाया गया है।

इनमें से 2,060 लोग आर्मेनिया के रास्ते और 301 लोग अजरबैजान के रास्ते आए। इन 2,361 लोगों में 1,041 भारतीय छात्र भी शामिल हैं, साथ ही तीन छात्र विदेशी (बांग्लादेश, श्रीलंका और गुयाना से एक-एक) हैं। वहीं, ईरान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि सोमवार से उत्तर-पूर्वी प्रांत खोरासन रजावी में मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिर से शुरू की जाएंगी।ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिससे पूरे देश में नागरिक उड्डयन सेवाएं रुक गई थीं।

बांग्लादेश में तेल संकट को लेकर बिगड़े हालात, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगीं

एजेंसी

ढाका । ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं है। बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। तेल की कमी होने की आशंका के चलते लोग घबराहट में ईंधन खरीद रहे हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने बार-बार आश्वासन दिया है कि ईंधन की आपूर्ति स्थिर है, फिर भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। सरकार ने 18 अप्रैल को पावर, एनर्जी और मिनरल रिसोर्स डिवीजन से जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। डीजल की कीमत में प्रति लीटर 15 बांग्लादेशी टका की बढ़ोतरी की गई है, जबकि ऑक्टेन 20 टका, पेट्रोल 19 टका और केरोसिन 18 टका प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। नई दरें रात से लागू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्राइवेट कार मालिकों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और छोटे बिजनेस मालिकों समेत कई लोगों को फ्यूल भरवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे काम के समय और कमाई में काफी नुकसान हो रहा है। मीरपुर में एक राइड शेयरिंग ड्राइवर अब्दुल करीम ने कहा कि लंबी देरी से उनकी इनकम पर असर पड़ा है। बांग्लादेशी अखबार द ढाका ट्रिब्यून ने उनके हवाले से कहा, 'मैं आमतौर पर एक दिन में 12 से 14 ट्रिप करता हूं, लेकिन अब फ्यूल के लिए लाइन लगने में ही मेरे दो से तीन घंटे खराब हो जाते हैं। मेरी रोज की कमाई लगभग 30 फीसदी कम हो गई है। ' उत्तरा की स्कूल टीचर शहाना बेगम ने अपने रोज के आने-जाने की परेशानी बताते हुए कहा, 'मैंने कल शाम फ्यूल भरवाने के लिए लगभग डेढ़ घंटे इंतजार किया। रोज के कामों की प्लानिंग करना तनाव भरा होता जा रहा है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि लाइन कितनी लंबी होगी। ' बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शॉर्ट-टर्म डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट और डिमांड में बढ़ोतरी से ऑपरेशन पर दबाव पड़ा है। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर ढाका ट्रिब्यून से कहा, 'पूरे देश में फ्यूल की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में डिमांड तेजी से बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट शेड्यूलिंग की दिक्कतों की वजह से कुछ स्टेशनों को सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ रहा है। 'ढाका में मीडिया से बात करते हुए पावर, एनर्जी और मिनरल संसाधन मंत्री इकबाल हसन महमूद टुकू ने स्थिति को युद्ध के समय जैसा बताया। उन्होंने कहा, 'फ्यूल विदेशी करेंसी से ही खरीदना होगा। कीमतें थोड़ी बढ़ाकर, हम हालात को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध का नतीजे दुनियाभर में होते हैं। ' बांग्लादेश के कंज्यूमर्स एसोसिएशन के ऊर्दा सलाहकार एम. शमसुल आलम ने फ्यूल की कीमतें बढ़ाने के फैसले को भरोसे का उल्लंघन बताया और कहा कि सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया था ।

सीजफायर खत्म होने से पहले ईरान-अमेरिका में बातचीत जारी, गालिबफ का दावा-कई मुद्दों पर अभी मतभेद

एजेंसी

तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा दो हफ्ते का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ उसकी चल रही बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि यह भी कहा कि हम अंतिम फाइनल समझौते से अभी दूर हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने शनिवार (स्थानीय समयानुसार) को टीवी पर दिए एक भाषण में कहा कि दोनों पक्षों के बीच बड़े मतभेद अभी बने हुए हैं। गालिबफ ने कहा, 'बातचीत अभी तक किसी अहम मोड़ पर नहीं पहुंची है। कई कमियां हैं और कुछ बुनियादी बातें अभी बाकी हैं। '

गालिबफ का यह भी दावा है कि संघर्ष के हाल के हफ्तों में ईरान का पलड़ा भारी रहा। तेहरान अस्थायी सीजफायर के लिए तभी राजी हुआ, जब वॉशिंगटन ने उसकी शर्तें मान लीं। ईरान की रणनीतिक स्थिति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहा है, जबकि ईरान ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक अहम समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल बनाए रखा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा, ' 'दुश्मन की हर कोशिश हम पर अपनी शर्तें थोपने की थी और यह जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को दर्ज कराएं। इसलिए बातचीत भी संघर्ष का एक तरीका है।

इस बीच, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) ने कहा कि देश तब तक होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले ट्रैफिक पर कंट्रोल और निगरानी रखने के लिए तैयार है, जब तक कि युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और इलाके में पक्की शांति नहीं आ जाती।

ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान ईरान के मुख्य मिलिट्री कमांड, खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट पर सख्त कंट्रोल फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद आया है। न्यूज एजेंसीकी रिपोर्ट के मुताबिक, एसएनएससी ने कहा कि वह जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करेगा। इसके तहत जहाजों की जानकारी ली जाएगी, प्रवेश और निकास के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा और अपने नियमों व युद्धकालीन प्रोटोकॉल के अनुसार समुद्री यातायात को संचालित किया जाएगा।

उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट

एजेंसी

टोक्यो। पश्चिम एशिया में संकट के बीच उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी सिनपो इलाके से दागी गईं। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट मोड में आ गए। उत्तर कोरिया ने एक महीने में चौथी बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने बताया कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिसाइल लॉन्च से संबंधित जानकारी साझा कर विश्लेषण कर रहे हैं और हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

पीएम साने ताकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आज सुबह करीब 06:00 बजे (जापानी समयानुसार), उत्तर कोरिया से कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गईं। माना जा रहा है कि जो चीजें बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं, वे जापान के ईईजेड के बाहर पहले ही गिर चुकी हैं और अभी, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जानकारी का विश्लेषण करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ' उन्होंने बताया, 'सरकार के तौर पर लॉन्च के तुरंत बाद हमने जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस के क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को बुलाया।

इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में बफर जोन का नक्शा किया जारी, सीजफायर के बावजूद ऑपरेशन किए तेज

एजेंसी

यरूशलम। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया है। इसमें लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक फैला एक बड़ा इलाका दिखाया गया है, जो लेबनान के भूमध्यसागरीय पानी से लेकर सीरियाई बॉर्डर के पास माउंट हरमोन इलाके तक एक लंबी पट्टी की तरह फैला हुआ है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल कॉट्ज ने कहा है कि इजरायल इस इलाके से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा, भले ही गुरुवार और शुक्रवार की आधी रात को लोकल टाइम पर एक अस्थायी सीजफायर लागू हुआ हो। कॉट्ज ने यह भी कहा कि इजरायल इस इलाके में घरों और बिल्डिंग्स को गिरा देगा। उन्होंने इसकी तुलना गाजा पट्टी में हुई कार्रवाइयों से की और चेतावनी दी कि इजरायली सेना हिज्बुल्लाह का सदस्य माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगी। सेना ने एक बयान में कहा कि पांच डिवीजन, नौसेना बल के

साथ, अभी लेबनानी इलाके में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन बनाने के लिए काम कर रहे हैं; इसका मकसद उत्तरी इजरायल के समुदायों के लिए सीधे खतरों को नाकाम करना है। मैप में नकौरा-रास अल-बयादा कोस्टलाइन से दूर एक समुद्री हिस्सा शामिल है, जो एक नेवल हिस्सा दिखाता है। बफर जोन बिंट जेबिल, ऐता अल-शाब और खियाम जैसे खास शहरों और कस्बों के उत्तर में है और कुछ क्षेत्रों में लिटानी नदी तक फैला हुआ है, जिसमें कई गांव और रिज लाइनें शामिल हैं। लेबनान और सीरिया ने इस कदम को मंजूरी नहीं दी है। सीजफायर के बावजूद, लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी (एनएनए) के मुताबिक, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए।

बिंत जबील में सुरक्षा क्षेत्र खाली कराने के नाम पर बलों ने घरों को गिराना जारी रखा, जबकि भारी तबाही झेल चुके शहर में टैंक गश्त करते रहे। सैनिकों ने अल-बयादा और अल-नकूरा में भी मकानों को विस्फोट से उड़ाया, सड़कों को मिट्टी के ढेर लगाकर बंद किया और कूनीन कस्बे पर गोलाबारी की। इस घटनाक्रम पर इजरायल की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह मैप वॉशिंगटन के इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के सीजफायर की घोषणा के तीन दिन बाद जारी किया गया।

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच मार्च की शुरुआत से भीषण तनाव जारी था। नवंबर 2024 में शुरू हुए पिछले सीजफायर के दौरान, इजरायल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में लगभग रोजाना हमले जारी रखे थे।

page 1 and 8 Apr 21_page 1 Mar 25 final ds.qxd 4/21/2026 1:44 AM Page 2

स्थानीय समाचार

अमरनाथ यात्रा 2026 लंगर संगठनों से जबरन अंडरटेकिंग लिए जाने के आरोप, SABLO ने उठाए गंभीर सवाल

लुधियाना। श्री अमरनाथ बरफानी लंगर्स ऑर्गेनाइजेशन (SABLO) ने श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 के लिए लंगर संगठनों को अनुमति देने की प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही है और एक विवादित अंडरटेकिंग पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं।

SABLO के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि (25 मार्च 2026) के तीन सप्ताह बाद भी न तो चयन मानदंड घोषित किए गए हैं और न ही अनुमति प्रक्रिया की कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। इसके विपरीत, कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा NGOs से एक अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करवाने की जानकारी सामने आई है, जिसे अनुमति के लिए अनिवार्य बताया जा रहा है।

संगठन का कहना है कि उक्त अंडरटेकिंग एकतरफा, दमनकारी एवं संगठनों के अधिकारों के विरुद्ध है। इसमें अनुमति को अस्थायी एवं रद्द करने योग्य बताया गया है, पूर्व सेवाओं के आधार पर कोई अधिकार न मानने तथा किसी भी दायित्व के लिए बोर्ड को पूर्ण क्षतिपूर्ति देने जैसी शर्तें शामिल हैं।

SABLO ने इसे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और वैधता पर प्रश्नचिह्न बताते हुए आरोप लगाया कि NGOs पर दबाव, भय एवं अनुचित प्रभाव डाला जा रहा है। संगठन ने यह भी आशंका जताई कि एक समानांतर एवं अनधिकृत तंत्र इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है।

SABLO की प्रमुख मांगें-अंडरटेकिंग की वैधता पर तत्काल लिखित स्पष्टीकरण

यदि अधिकृत नहीं है तो जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई

यदि अधिकृत है तो ऐसी शर्तों को तत्काल वापस लिया जाए

पूरी अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए

SABLO ने कहा कि इस स्थिति से वर्षों से सेवा कर रहे लंगर संगठनों में भय और असमंजस का माहौल बन गया है। संगठन ने श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड से इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर स्पष्टता प्रदान करने और प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने की मांग की है।

पुलवामा में डीआईजी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

श्रीनगर, 20 अप्रैल (हि.स.)। दक्षिण कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक जावेद इकबाल मट्टू ने सोमवार को पुलवामा में अपराध, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों की व्यापक समीक्षा की जिसमें अधिकारियों को सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। दक्षिण कश्मीर रेंज (एस. के. आर.) के पुलिस उप महानिरीक्षक जावेद इकबाल मट्टू-आई. पी. एस. ने आज जिला पुलवामा का दौरा किया और जिला पुलिस लाइन (डी. पी. एल.) पुलवामा के सम्मेलन कक्ष में एक व्यापक अपराध और सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एस. एस. पी. पुलवामा सुश्री तनुश्री-आई. पी. एस. के साथ-साथ पुलवामा पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिनमें पर्यवेक्षी अधिकारी, एस. एच. ओ. और जाँच अधिकारी शामिल थे ने भाग लिया। बैठक के दौरान समग्र अपराध परिदृश्य, मामलों की जांच, एनडीपीएस मामलों और निवारक उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीआईजी ने जिले में आतंकवाद विरोधी प्रयासों और आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य की भी समीक्षा की।

राष्ट्र-विरोधी तत्वों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, क्षेत्र को मजबूत करने और खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने और किसी भी सुरक्षा चुनौती के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

जीडीसी हीरानगर में पोषण व नशा मुक्ति पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित

कठुआ, 20 अप्रैल (हि.स.)। जीएलडीएम डिग्री कॉलेज हीरानगर में पोषण पखवाड़ा और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा खन्ना के स्वागत संबोधन से हुई, जिसके बाद नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई।

मुख्य वक्ता के रूप में प्रो. एकता गुप्ता ने संतुलित आहार, स्वस्थ जीवनशैली, स्क्रीन टाइम में कमी और नशे से दूर रहने के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन अंशिका वर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. शापिया शमीम ने प्रस्तुत किया। इस दौरान कॉलेज के प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया।

महिला आरक्षण – प्रश्नोत्तरी

1. 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में कौन-कौन से विधेयक पेश किए?

16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन प्रमुख विधेयक पेश किए-

• संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026

• परिसीमन विधेयक, 2026

• संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026

2. केंद्र सरकार द्वारा यह तीनों बिल वर्तमान समय में क्यों लाया गया?

नारीशक्ति वंदन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना केबाद, होने वाले परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। अगर

केंद्र सरकार 2026 जनगणना और फिर उसके आधार पर परिसीमन की प्रतीक्षा करती तो महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ 2029 के आम चुनाव में भी नहीं मिल पाता, इसीलिए देश की आधी-आबादी को जल्द-से-जल्द लाभ पहुँचाने के लिए इसको 2026 जनगणना के आधार पर होने वाले

परिसीमन से अलग (Delink) करना जरूरी था।

3. अगर यह तीनों विधेयक सदन से पारित हो जाते तो इससे देश को क्या लाभ होता?

यदि ये तीनों विधेयक सदन से पारित हो जाते, तो राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद ये कानून बन जातेऔर देश की महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव में ही 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकता था, जिससे उनका लंबे समय से प्रतीक्षित अधिकार प्राप्त होता।

4. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ अभी परिसीमन की बात क्यों लायी गई? सरकार इतनी ज्यादा

सीटें क्यों बढ़ा रही थी? परिसीमन का अर्थ है किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन आवश्यक है। लोक सभा में सीटों की संख्या को 1976 में 550 निर्धारित किया गया था। 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी। आज यह 140 करोड़ है। इसलिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना महत्वपूर्ण है। इससे संसद में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

5. क्या केंद्र सरकार Delimitation Commission Act में बदलाव करके राजनीतिक लाभ लेना

चाहती थी? यह सरकार जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तब क्यों बिल लाई, क्या इसका तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हो रहे चुनाव पर असर होगा ? केंद्र सरकार ने Delimitation Commission Act में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि पुराने कानून को यथावत रखा। परिसीमन आयोग की सिफारिशें तभी लागू होतीं जब संसद उन्हें मंजूरी देती और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती। वर्तमान में हो रहे चुनावों, जैसे तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, पर इस

प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 2029 तक सभी चुनाव मौजूदा व्यवस्था और वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही कराए जाएंगे।

6. लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के पीछे मुख्य कारण और तर्क क्या थे?

यह प्रस्ताव जनसंख्या के अनुपात में सीटों के विस्तार पर आधारित था। एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात अभी की तरह बना रहता। इस सिद्धांत के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान की 543 से बढ़कर लगभग 815 होती। इसलिए लोक सभा में सीटों की संख्या की अधिकतम सीमा 550 से बढ़कर 850 की जा रही थी।

7. क्या नए परिसीमन प्रस्ताव में दक्षिण भारतीय राज्यों या छोटे राज्यों को नुकसान होता?

नहीं, सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 प्रतिशत वृद्धि होती। दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आती। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, दक्षिणी राज्यों के पास वर्तमान में लोक सभा में 23.76 प्रतिशत सीट हैं। विधेयकों के पारित होने के बाद यह बढ़कर लगभग 23.87 प्रतिशत हो जातीं। उदाहरण के तौर पर तमिल नाडु की सीटें भी इसी अनुपात में बढ़तीं और राज्य को कोई नुकसान नहीं होता।

# राज्य	सीट संख्या (कुल 543)	वर्तमान 543 का प्रतिशत	लगभग 50% की वृद्धि के बाद	सीट संख्या प्रस्तावित 816	का प्रतिशत
1. कर्नाटक	28	5.15%	42	5.14%	
2. आंध्र प्रदेश	25	4.60%	38	4.65%	
3. तेलंगाना	17	3.13%	26	3.18%	
4. तमिल नाडु	39	7.18%	59	7.23%	
5. केरलम	20	3.68%	30	3.67%	
कुल	129	23.76	(लगभग 24%)195	23.87	(लगभग 24%)

543 सीट से बढ़कर 816 सीट (50% वृद्धि)

8. क्या नए परिसीमन प्रस्ताव से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान होता?

नहीं, नए परिसीमन प्रस्ताव से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को कोई नुकसान नहीं होता।

प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात में वृद्धि (50%) की बात थी, जिससे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व प्रतिशत घटने के बजाय यथावत रहता या थोड़ा बढ़ता।

9. क्या नए परिसीमन प्रस्ताव से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिनिधित्व और अधिकारों को नुकसान पहुंचता?

हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न वर्गों के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण और वृद्धि होती है। यदि ये तीनों विधेयक पारित हो जाते, तो लगभग 850 सीटों वाले सदन में आरक्षित सीटों की संख्या 131 से बढ़कर करीब 205 हो जाती, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में वृद्धि होती, किसी प्रकार का नुकसान नहीं।

10. जाति जनगणना को टालने के लिए सरकार यह संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी?

केंद्र सरकार तीन महीने पहले ही जाति जनगणना की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, इसलिए इसे टालने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान जनगणना प्रक्रिया में पहले घरों की गणना की जा रही है औरइसके बाद जब व्यक्तियों की गणना होगी, तब जाति से संबंधित जानकारी भी पूरी तरह दर्ज की जाएगी।

11. विपक्ष की निरंतर मांग के बावजूद महिला आरक्षण के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा क्यों नहीं दिया गया?

भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण की नीतियाँ संविधान में निर्धारित सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित हैं।

12. सरकार ने महिला आरक्षण को वर्ष 2029 तक टालने के बजाय 2024 के आम चुनावों में ही इसे तुरंत लागू क्यों नहीं कर दिया, इसे 2011 की आधार पर ही क्यों नहीं लागू किया गया?

आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। परिसीमन एक व्यापक चर्चा आधारित प्रक्रिया है। परिसीमन पूरा करने में लगभग दो वर्ष लगते हैं। इसलिए महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन विधेयक के साथ ये तीनों विधेयक लाए गए थे।

13. जब 2024 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं होना था, तो 2023 में महिला आरक्षण विधेयक क्यों लाया गया?

2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई। नए संसद भवन में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ और राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिली। सबने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और इस प्रकार नारी शक्ति वंदन विधेयक से अधिनियम बन गया।

14. महिला आरक्षण को केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में लागू करने के लिए अलग से 39;केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 39; क्यों लाया गया था?

जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं अलग 39;UT Act39; से संचालित होती हैं । इन विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए क्रमशः लगभग 38, 23 और 10 सीटें आरक्षित करने के लिए यह तकनीकी संशोधन अनिवार्य था, इसीलिए अलग से 39 केंद्र शासित प्रदेश विधेयक39; लाया गया था ।

एसीबी की बड़ी कार्रवाई-पहलगाम खाद्यान्न गबन मामले में 5 दोषी करार, कुपवाड़ा में पूर्व बीडीओ सहित 5 के खिलाफ चार्जशीट

जम्मू, 20 अप्रैल (हि.स.)। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। अनंतनाग की विशेष एंटी करप्शन अदालत ने पहलगाम सर्किल में खाद्यान्न गबन मामले में पांच तत्कालीन स्टोरकीपरों को दोषी करार दिया है।

अदालत ने पाया कि आरोपियों ने वर्ष 1989 के दौरान खाद्यान्न और खाली बोरों की हेराफेरी कर सरकारी खजाने को लगभग 3.64 लाख का नुकसान पहुंचाया। यह मामला 1990 में दर्ज हुआ था और लंबी सुनवाई के बाद अब फैसला आया है। सजा की अवधि पर 24 अप्रैल 2026 को सुनवाई होगी। वहीं एक अन्य मामले में एसीबी ने कुपवाड़ा के तत्कालीन बीडीओ सहित पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सरकारी विकास कार्यों के नाम पर फर्जी दस्तावेज और रिकॉर्ड तैयार कर करीब 4.86 लाख की राशि का गबन किया। एसीबी के अनुसार आरोपियों ने फर्जी फंड ट्रांसफर ऑर्डर बनाकर पैसे को निजी खातों में ट्रांसफर किया और सरकारी रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ की। इस मामले में तीन सरकारी अधिकारी और दो निजी व्यक्ति शामिल हैं। एसीबी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश जाता है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी

ईश्वर भक्ति और विद्वानों का संग ही सच्चे सुख का मार्ग : स्वामी राम स्वरूप जी

कठुआ, 20 अप्रैल (हि.स.)। 78 दिवसीय वेदों पर आधारित यज्ञ के दौरान योगाचार्य स्वामी राम स्वरूप जी ने कहा कि सच्चा सुख केवल ईश्वर भक्ति और विद्वानों के ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है।

वेद मंदिर योल में आयोजित यज्ञ के दौरान उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या करते हुए बताया कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो वेदों के ज्ञान से प्रेरित होकर धर्म, सुरक्षा और सदाचार का पालन करता है। ऐसे लोग ही समाज में विद्वान, ऋषि और तपस्वी कहलाने योग्य होते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदैव विद्वानों के संग में रहकर वेद ज्ञान सीखना और उसे जीवन में अपनाना चाहिए। बिना विद्वानों के मार्गदर्शन और ईश्वर की उपासना के न तो सच्चा धन प्राप्त हो सकता है और न ही स्थायी सुख। स्वामी जी ने यजुर्वेद के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यज्ञ के माध्यम से अर्जित शुद्ध और कल्याणकारी धन ही मनुष्य को वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है।

कठुआ पुलिस ने लापता युवती को ढूंढकर परिवार से मिलाया

कठुआ, 20 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने बसोहली क्षेत्र में एक सराहनीय कार्रवाई करते हुए लापता युवती को खोजकर सकुशल उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को मोहम्मद यूसुफ निवासी प्लाख मोरा चकियां, तहसील बसोहली ने अपनी 18 वर्षीय बेटी शहनाज बीबी के लापता होने की शिकायत थाना बसोहली में दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना बसोहली की टीम ने एसएचओ के नेतृत्व में और एसडीपीओ बसोहली के मार्गदर्शन में विभिन्न स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। तकनीकी सहायता और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने युवती को ढूंढ निकाला। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया ग

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान क्रियान्वयन में कठुआ जिला बना अव्वल, 81 प्रतिशत स्कोर हासिल

कठुआ, 20 अप्रैल (हि.स.)। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन में कठुआ जिला संभाग स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है। जिले ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वयं मूल्यांकन में 81 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। यह उपलब्धि जम्मू में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान सामने आई, जिसका आयोजन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय जम्मू द्वारा किया गया। कार्यशाला में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा गुरदेव कुमार ने कहा कि तंबाकू मुक्त संस्थान बनाना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं संयुक्त निदेशक (ईई) रोमी कुमार ने स्कूल स्तर पर निरंतर निगरानी और जागरूकता पर जोर दिया। कठुआ टीम का नेतृत्व जिला नोडल अधिकारी मोनिका खोसला ने किया, जिसमें जोनल नोडल अधिकारी सुनीता कुमारी, मीतू गुप्ता और अजय कुमार शामिल रहे। मुख्य शिक्षा अधिकारी केवल कृष्ण ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए 100 प्रतिशत तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प दोहराया।

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महानपुर में जागरूकता रैली आयोजित

कठुआ, 20 अप्रैल (हि.स.)। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ द्वारा महानपुर में एंटी ड्रग जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के निर्देशन में आयोजित हुआ। रैली को एसडीपीओ बसोहली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जीएचएसएस महानपुर और आदर्श विद्या निकेतन के विद्यार्थियों, स्थानीय नागरिकों व जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जम्मू-कश्मीर में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में तेजी के निर्देश

जम्मू, 20 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को तेज और सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए।

सिविल सचिवालय जम्मू में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने जिला स्तर पर एफआरए सेल्स के गठन में तेजी लाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और पात्र

लाभार्थियों को शीघ्र अधिकार प्रदान करने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत किया जाए और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। साथ ही, अस्वीकृत दावों का पूरा डेटा तैयार कर कारणों का विश्लेषण करने के भी निर्देश दिए गए। राणा ने अधिकारियों को नियमित निगरानी और समय-सीमा का सख्ती से पालन करते हुए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा।

भद्रवाह में छात्रों ने रंगों से दी नशामुक्त समाज की पुकार

आमिर इक़बाल ख़ान

भद्रवाह, 20 अप्रैल । नशे की बढ़ती समस्या के खिलाफ एक सशक्त संदेश देने के लिए भद्रवाह के छात्रों ने अपनी कलम और रंगों को हथियार बनाया। सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे '100 दिन नशा मुक्त अभियान' के अंतर्गत भारतीय विद्या मंदिर (बीवीएम) में आयोजित चित्रकला एवं जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों और नशामुक्त समाज की आशा को चित्रों में उकेरा।

कार्यक्रम का संचालन जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी डोडा के मार्गदर्शन में तथा तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी भद्रवाह शाहनवाज़ अहमद की देखरेख में हुआ। अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।

विद्यालय की प्राचार्य प्रिया कोहली ने इस अवसर पर कहा कि शैक्षणिक संस्थान समाज को स्वस्थ और जिम्मेदार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों को सतर्क रहने, सही निर्णय लेने और अपने मोहल्लों में नशामुक्त वातावरण बनाने में योगदान देने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम का समापन छात्रों की उत्साही भागीदारी और उनके

सशक्त संदेशों से भरे चित्रों की सराहना के साथ हुआ। प्रशासन ने विद्यार्थियों की रचनात्मक पहल को समाज में नशामुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।